

वीकली वन लाइनर्स 13 से 19 जुलाई, 2026

EPFO VISHWAS 2026 क्या है? इसके फायदे, एलिजिबिलिटी और खास बातें

विश्वास 2026 स्कीम, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) द्वारा शुरू की गई एक वन-टाइम स्कीम है, का मकसद सभी एम्प्लॉयर्स को उनके उन मामलों को सुलझाने में मदद करना है जो लंबे समय से डैमेज और पेनल्टी से जुड़े पेंडिंग हैं। यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लिटिगेशन को कम करने, अपनी मर्जी से कम्प्लायंस को बढ़ावा देने और भारत में सोशल सिक्योरिटी के मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के मकसद से शुरू की है। विश्वास स्कीम, जो 29 जून को शुरू हुई थी, ने नई पेनल्टी शुरू की है जो ज्यादातर मामलों में लागू मौजूदा पेनल्टी से कम है।

विश्वास 2026 क्या है?

विश्वास 2026 विवादों को सुलझाने की एक पहल है जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शुरू किया है। इस स्कीम का मकसद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविज़न्स एक्ट, 1952 के सेक्शन 14B के तहत हुए नुकसान और सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के सेक्शन 128 के तहत लगाए गए जुर्माने से जुड़े झगड़ों को सुलझाना है।

इस स्कीम को 29 जून 2026 को GSR 525(E) के ज़रिए EPF स्कीम, 2026 के हिस्से के तौर पर नोटिफ़ाई किया गया है और यह नोटिफ़िकेशन की तारीख से छह महीने के लिए वैलिड है।

EPFO ने VISHWAS 2026 क्यों लॉन्च किया?

इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य लंबे समय से अनसुलझे झगड़ों को सुलझाना है, साथ ही ऑर्गनाइजेशन को अपनी मर्जी से EPF नियमों को मानने के लिए मोटिवेट करना है।

मुख्य उद्देश्य हैं,

- EPF मुआवज़े और जुर्माने से जुड़े झगड़ों के मामलों में कमी लाना
- एम्प्लॉयर्स को बिना किसी दबाव के नियम पूरे करने में मदद करना
- मामलों का तेज़ी से समाधान
- कर्मचारियों का समर्थन
- टेक्नोलॉजी की मदद से सेटलमेंट को आसान बनाना
- भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में सुधार

EPFO ने फाइन रेट कम करने का प्रस्ताव दिया है ताकि ऑर्गनाइजेशन लंबे झगड़ों से गुज़रने के बजाय फाइन भर सकें।

विश्वास 2026 स्कीम के तहत कौन से केस कवर होने के लिए एलिजिबल हैं?

इस स्कीम में केस की चार कैटेगरी हैं, जो नीचे बताई गई हैं, अदालतों में अभी भी चल रहे मामले

जिन विवादों में नुकसान की पेनल्टी लगाने के बारे में फ़ैसला सुनाया जा चुका है, उन्हें कोर्ट और ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा रही है।

वसूली के लिए सौंपे गए अंतिम आदेशों के मामले

ऐसे केस जिनमें पेनल्टी या डैमेज के फाइनल ऑर्डर पास हो गए हैं, लेकिन रिकवरी अभी भी पेंडिंग है या पूरी नहीं हुई है। इसमें रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) केस भी शामिल हैं।

नोटिस जारी करना लेकिन अंतिम आदेश लंबित

मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक कोई फ़ाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है।

ऐसे मामले जहां नोटिस जारी नहीं किए गए हैं

जिन मामलों में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, वे भी इस स्कीम के तहत आते हैं।

विश्वास 2026 के अनुसार कम पेनल्टी दरें

इस स्कीम का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि 14 जून 2024 से पहले होने वाले डिफ़ॉल्ट के लिए पेनल्टी और डैमेज रेट में काफ़ी कमी आएगी।

बदले हुए रेट इस प्रकार हैं,

चूक की अवधि	रियायती दंड दर
2 महीने से कम	0.25% प्रति माह
2 महीने से ज्यादा और 4 महीने तक	0.50% प्रति माह
4 महीने से अधिक	1.00% प्रति माह

इन रियायती दरों का मकसद बाकी विवादों का तेज़ी से समाधान करना है।

नियोक्ताओं के लिए पात्रता मानदंड

विश्वास 2026 के नियमों का फ़ायदा उठाने के लिए, कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

एम्प्लॉयर्स को ये करना होगा,

स्कीम के लिए अप्लाई करने से पहले, पक्का करें कि EPF & MP एक्ट, 1952 के सेक्शन 7Q या सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के सेक्शन 127 के तहत लागू कानूनी ब्याज का पूरा डिफ़ॉल्ट हो गया है।

एक अंडरटेकिंग दें जिसमें लिखा हो कि स्कीम के तहत निपटाए गए झगड़ों के बारे में कोई और अपील शुरू नहीं की जाएगी। तय समय के अंदर स्कीम के लिए अप्लाई करें।

अगर एलिजिबिलिटी की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो कोई एम्प्लॉयर VISHWAS 2026 के तहत बेनिफ़िट पाने के लिए इनएलिजिबल हो सकता है।

योजना से छूट प्राप्त मामले

कुछ खास केस ग्रुप को भी VISHWAS 2026 से बाहर रखा गया है, जैसे,

- ऐसे मामले जहां पेमेंट की ज़िम्मेदारी पहले ही तय हो चुकी है।
- बेईमानी से काम करने या जानबूझकर गलत जानकारी देने से पैदा हुए मामले।
- ऐसे मामले जहां प्रोविज़न के तहत स्टैच्युटरी इंटररेस्ट पूरी तरह से जमा नहीं किया गया है।
- इन एक्सक्लूज़न से यह पक्का होता है कि स्कीम सिर्फ़ असली मामलों को ही अपनी मर्जी से पालन करने में मदद करती है।

ईपीएफओ विश्वास 2026 के लिए आवेदन कैसे करें

इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयर्स को EPFO के पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होगी।



ALL EXAMS, **ONE** SUBSCRIPTION

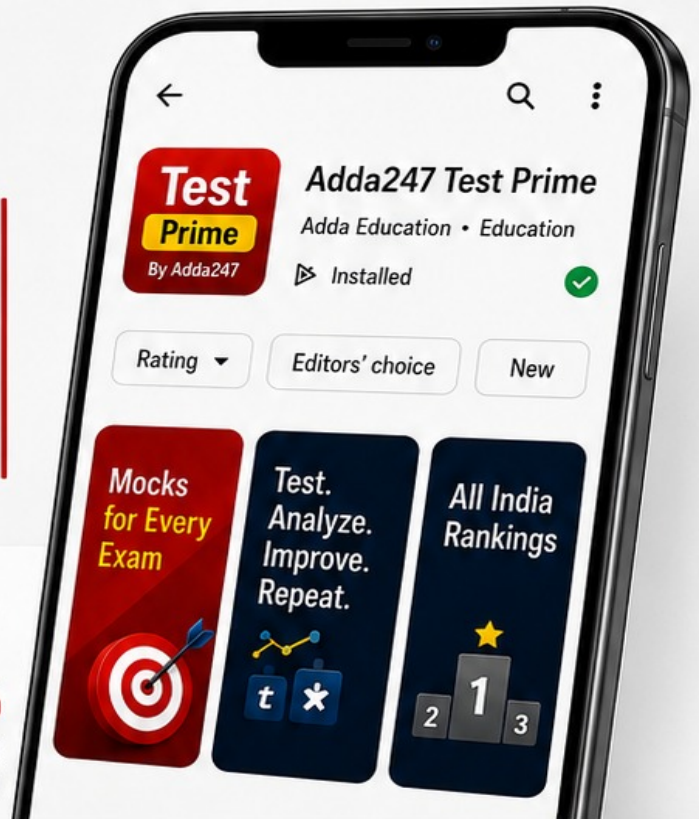


Test. Analyze. Improve. Repeat.



*Don't just
prepare.
Perform.*

Test Prime – built only
for mock tests.



1,50,000+
Mock Tests



25,000+
Previous Year
Papers



800+
Exam
Covered



500%
Refund on
Selection



5 lakh+
Free Quizzes



Daily
Free PDFs



Top Alerts
Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- ✓ Multilingual
- ✓ Detailed Solution
- ✓ Strong and Weak Areas
- ✓ All India Rankings



Safe & Reliable



Trusted by
Lakhs of Aspirants

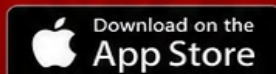
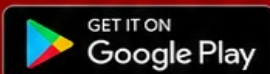


Your Success,
Our Mission



**DOWNLOAD
TEST PRIME**

Your Success Partner!



डिजिटल प्रक्रिया में शामिल हैं,

- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) या ई-साइन के ज़रिए लॉग इन करना।
- ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करना।
- डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल वेरिफिकेशन।
- EPFO की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रोसेसिंग।
- EPFO साइट से सेटलमेंट के ऑर्डर जारी करना।

उम्मीद है कि यह पेपरलेस प्रोसेस सिस्टम से देरी को दूर करने और अच्छे से काम करने में मदद करेगा।

एम्प्लॉयर्स की मदद के लिए VISHWAS के लिए डेडिकेटेड सेल।

EPFO ने इस पहल को आसानी से लागू करने के लिए अपने ज़ोनल, रीजनल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में खास VISHWAS सेल बनाए हैं।

ये कोशिकाएँ,

- एम्प्लॉयर्स को एप्लीकेशन फाइल करने में मदद करें।
- डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करने के लिए।
- एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए।
- समस्याओं का समय पर समाधान पक्का करना।
- उन्हें पूरे प्रोसेस में गाइड करना।

EPFO ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें ज़ोनल और हेडक्वार्टर से ऑपरेशन की मॉनिटरिंग शामिल है।

कैबिनेट ने मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दी: खास बातें, फ़ायदे, फ़ायदे और उम्मीद के मुताबिक असर

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में यूनियन कैबिनेट ने मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है। इस प्लान को ₹ 62,500 करोड़ की फ़ाइनेंशियल मदद मिली है, जिसका मकसद लोकल मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, वैल्यू एडिशन बढ़ाना, सप्लाय चैन की एफ़िशिएंसी बढ़ाना, इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करना और भारत को मोबाइल मैनुफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनाना है। यह डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग के लिए सफल प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI) प्लान के पूरा होने के ठीक बाद हुआ है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर सरकार की कोशिशों को दिखाता है।

मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) क्या है?

मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) भारत में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई स्कीम है।

इस स्कीम को 15 जुलाई, 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत, सरकार का मकसद परफॉर्मेंस से जुड़े रिवॉर्ड के ज़रिए मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है।

MPMS का मकसद भारत को मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स बनाने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D, और ब्रांड बनाने के फ़ील्ड में एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ हासिल करने में मदद करना है।

इस स्कीम का मकसद 2026-27 से पांच साल में प्रोजेक्ट के नतीजे पाने के लिए भारत को ऑपरेशनल बनाना है।

एमपीएमएस का परिचय

भारत शेयर के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर बन गया है, क्योंकि भारत में बनने वाले 99% मोबाइल फ़ोन देश में ही बिकते हैं।

हालांकि पिछले दस सालों में मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी में सुधार करना एजेंडा आइटम में से एक बना हुआ है।

MPMS का उद्देश्य था,

- मोबाइल फ़ोन निर्माण क्षमताओं को बढ़ाना
- मुख्य कंपोनेंट्स के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दें
- आयातित वस्तुओं पर कम निर्भरता
- एक लचीली सप्लाय चैन बनाएं
- इनोवेशन पर भरोसा करने वाले भारतीय इन्वेस्टर को सपोर्ट करें
- स्वदेशी डिजाइन और अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भारत की स्थिति को बेहतर बनाना।

इस स्कीम की शुरुआत भारत को दुनिया भर में मैनुफैक्चरिंग के लिए एक भरोसेमंद जगह बनाने के लंबे समय के मकसद से भी जुड़ी थी।

मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) की मुख्य विशेषताएं हाल ही में मंज़ूर हुई स्कीम में कई इंसेंटिव दिए गए हैं, जो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस में टेक डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।

बजट

- बजट की कुल राशि: ₹ 62,500 करोड़

योजना अवधि

- पांच साल
 - वित्तीय वर्ष 2026-2027 से वित्तीय वर्ष 2030-2031 तक
- योग्य बिक्री के लिए प्रोत्साहन
- मैनुफैक्चरर्स को नीचे दिए गए तरीके से रीइंबर्समेंट किया जाएगा,
- भारत में बने मोबाइल फ़ोन की क्वालिफाइड बिक्री पर 2.25% से 5% तक की छूट।
 - इंसेंटिव रेट कैटेगरी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से तय होते हैं।

घरेलू सोर्सिंग के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन

लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, कंपनियों को ये मिल सकता है,

- प्रोडक्शन के खास पार्ट्स की लोकल सोर्सिंग से जुड़े 1.5% तक ज़्यादा इंसेंटिव।
- ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा बेहतर सप्लाय चैन बनाने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के इरादे से किया गया है।
- इंडियन इंडस्ट्रीज़ से फंडरेजिंग
- इस तरह, टेक प्रोग्रेस में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, सरकार उन कंपनियों को एक्स्ट्रा फंडिंग दे सकती है जो प्रोडक्ट डिज़ाइन और R&D इनिशिएटिव पर पैसा खर्च करती हैं।
- कुछ भारतीय ब्रांड्स को क्वालिफाइड सेल्स के लिए रीइंबर्समेंट का एक्स्ट्रा 3% मिल सकता है।

MPMS कैसे PLI स्कीम की सफलता पर आगे बढ़ता है

PLI स्कीम के लागू होने से कई बड़ी उपलब्धियां मिली हैं कई ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने भारत में अपना ऑपरेशन शुरू किया है।

मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। भारत अलग-अलग ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लायर चेन में अपनी जगह बना पाया।

बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चालू की गई, जिससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा हुई, खासकर भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। MPMS नाम की नई स्कीम PLI स्कीम से मिले नतीजों को और बेहतर बनाएगी।

भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन: फीचर्स, सेफ्टी, रूट और ग्लोबल महत्व

इंडियन रेलवे भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस ट्रेन को घरेलू टेक्नोलॉजी और हरियाणा के जींद में मौजूद हाइड्रोजन इकोसिस्टम की मदद से बनाया गया है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से बिजली बनाती है, जिसका एकमात्र बाय-प्रोडक्ट पानी की भाप है। इस ट्रेन में लगभग 2,600 यात्री बैठ सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन में लगभग ज़ीरो एमिशन के साथ सभी एडवांस्ड मल्टी-लेयर सेफ्टी सिस्टम लगे हैं। इसे रेलवे सिस्टम को ग्रीन बनाने के लिए क्लीन एनर्जी देने और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की दिशा में भारत का कदम माना जा सकता है।

भारत में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन के बारे में

भारत की हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन एक नेक्स्ट-जेन रेलवे गाड़ी है जो पुराने डीज़ल इंजन या ज़मीन के ऊपर लगे इलेक्ट्रिक सिस्टम के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके ऑनबोर्ड बिजली बनाती है।

नॉर्मल ट्रेनों के मुकाबले, ट्रेन में टैंक में स्टोर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके PEM (प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन) फ्यूल सेल्स के ज़रिए बिजली बनाता है।

इसका इस्तेमाल ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए किया जाता है, और इससे सिर्फ भाप निकलती है, जो इसे रेलवे के लिए सबसे साफ़ टेक्नोलॉजी में से एक बनाती है।

यह प्रोजेक्ट भारत में सस्टेनेबल और लो कार्बन ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक क्यों है?

इंडियन रेलवे ने अपने 99% से ज़्यादा ब्रॉड गेज नेटवर्क को इलेक्ट्रिफाई करने में काफ़ी तरक्की की है, जिससे डीज़ल का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन इस बदलाव को और भी बेहतर बनाती है,

- इसके ऑपरेशन के दौरान कार्बन एमिशन को रोकना।
- बोर्ड पर रहते हुए बिजली पैदा करना।
- क्लीन एनर्जी में बदलाव में भारत की मदद करना।
- देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो काबिलियत है, उसे साबित करना।
- नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में योगदान देना।
- देश के नेट ज़ीरो लक्ष्यों में मदद करने के लिए एक नई संभावना बनाना।

यह रेलवे प्रोपल्शन सिस्टम के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है, जो स्टीम से डीज़ल और अब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन प्रोपल्शन सिस्टम तक पहुंच गया है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन कैसे काम करती है?

डीज़ल ट्रेनों की तरह सिर्फ़ फ़ॉसिल फ्यूल के जलने के बजाय, इस ट्रेन में एक छोटा पावर प्लांट है जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) फ्यूल सेल्स से बना है।

प्रक्रिया इस प्रकार है,

- ट्रेन के स्टोरेज टैंक से हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जाता है।
- ऑक्सीजन हवा से मिलती है।
- इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है।
- बिजली पैदा होती है।
- बिजली को ट्रैक्शन मोटर्स में भेजा जाता है।
- बाय-प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ़ भाप और गर्मी निकलती है।

डीज़ल इंजन के उलट, इसमें आग नहीं लगती, कोई एमिशन नहीं होता और कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं निकलता।

संक्षेप में,

- हाइड्रोजन + ऑक्सीजन → बिजली + भाप + गर्मी

भारत की हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीकी जानकारी भारत ...

एक जगह से दूसरी जगह बड़े पैमाने पर पैसंजर ट्रांसपोर्ट के लिए नई हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हो गई है।

प्रमुख विशेषताएं

- ट्रेन की संरचना: 10 डिब्बे
- यात्री क्षमता: लगभग 2,600 यात्री
- पावर कारें: 2 हाइड्रोजन पावर कारें
- ट्रेलर कारें: 8
- पावर प्रोडक्शन: 1,200 kW (1,600 hp) प्रति पावर कार
- कुल पावर: 2,400 kW
- ऑपरेटिंग स्पीड: 75 km/h
- अधिकतम डिज़ाइन गति: 110 km/h

यह टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन ट्रेन को दुनिया भर में चल रही दूसरी हाइड्रोजन पैसंजर ट्रेनों से बड़ी बनाती है, जिनमें आम तौर पर सिर्फ़ दो से चार डिब्बे होते हैं।

मार्ग और संचालन

शुरुआत में यह ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे के तहत जींद से सोनीपत तक चलेगी।

मार्ग के प्रमुख स्टेशन

- जींद जंक्शन
- जींद शहर
- पांडु पिंडारा जंक्शन
- गोहाना जंक्शन
- भंभेवा
- बुटाना
- मोहन
- सोनीपत
- सोनीपत न्यू

89 किलोमीटर के सेक्शन को नॉर्मल रेलवे कंडीशन में हाइड्रोलिक पैसेंजर ट्रेनों की परफॉर्मेंस, सेफ्टी और एफिशिएंसी के असेसमेंट के लिए चुना गया है।

भारत की पहली हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सुविधा जींद में इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी खासियत हरियाणा के जींद में भारत में ट्रेनों के लिए सबसे बड़ा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सेंटर बनाना है। इंटीग्रेटेड सेंटर में शामिल हैं,

हाइड्रोजन उत्पादन

हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है, यह पानी को बिजली की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने का प्रोसेस है।

हाइड्रोजन स्टोरेज

बनाए गए हाइड्रोजन को खास तौर पर डिज़ाइन किए गए कंटेनर में स्टोर किया जाता है।

संपीड़न

हाइड्रोजन को लगभग 500 b का प्रेशर लगाकर कम्प्रेस किया जाता है।

ईंधन भरने

ट्रेन में ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल होने वाला हाइड्रोजन दो डिस्पेंसर से आता है जो एक ही समय में 350 bar पर काम करते हैं ताकि दोनों मोटर कारों में ईंधन भर जाए।

भंडारण क्षमता

सेंटर की कैपेसिटी लगभग 3000 kg है जो ट्रेन ऑपरेशन की रेगुलर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफी है।

एडवांस्ड मल्टी-लेवल सिस्टम के साथ सुरक्षा के तरीके

हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा जलने वाला होता है, इसलिए सुरक्षा पक्का करना ज़रूरी है।

इंडियन रेलवे ने लोगों की सुरक्षा और अपने ऑपरेशन के लिए कई अलग-अलग सेफ्टी सिस्टम बनाए हैं।

मुख्य सुरक्षा घटक

- रेगुलर हाइड्रोजन लीक का पता लगाना।
- फ्लेम डिटेक्शन डिवाइस।
- धुआं पता लगाने वाले डिवाइस।
- हीटिंग मॉनिटरिंग डिवाइस।
- हाइड्रोजन से डिवाइस बंद हो रहे हैं।
- लगातार वेंटिलेशन का मकसद गैस जमा होने से बचाना है।
- आग से बचाव के उपकरण।
- पानी स्प्रे करने वाले सिस्टम।
- ऑपरेशन का सामान्य तरीका नहीं।
- ट्रेन के केबिन में रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम।

कुल मिलाकर, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, डिफेंस इन डेपथ के इंटरनेशनल लेवल पर माने गए नियम को फॉलो करते हैं, जो सिर्फ एक एलिमेंट पर निर्भर रहने के बजाय एक पूरा सेफ्टी सॉल्यूशन देता है।

वैश्विक सुरक्षा विनियम

हाइड्रोजन इकोसिस्टम को भी दुनिया भर में माने गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जैसे,

- एनएफपीए-2
- आईएसओ 19880 श्रृंखला

यह सिस्टम PESO द्वारा दी गई कानूनी ज़रूरतों को भी पूरा करता है।

असल में काम शुरू करने से पहले, इस प्रोजेक्ट का सेफ्टी का इंडिपेंडेंट असेसमेंट एक थर्ड पार्टी ऑर्गनाइज़ेशन TÜV SÜD, जर्मनी ने किया है, जो दुनिया भर में जानी-मानी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है।

कैबिनेट ने यूरिया-2026 (NIPU-2026) के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी: खास बातें, फ़ायदे, मकसद और असर

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया-2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी (NIPU-2026) को मंजूरी मिलने के बाद, इस नई स्कीम का मकसद गैस-बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और भारत की फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। NIPU-2026 के लिए पिछली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बदलकर, सरकार का मकसद अपनी महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजना के हिसाब से यूरिया इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाना है।

यूरिया के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2026 (NIPU-2026) क्या है?

नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया-2026 (NIPU-2026) फर्टिलाइज़र डिपार्टमेंट की नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जिसका मकसद देश के अलग-अलग हिस्सों में नए गैस-बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को शुरू करने को बढ़ावा देना है।

इस पॉलिसी का मकसद मॉडर्न यूरिया प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट और सही तरीका देकर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर से इन्वेस्टमेंट लाना है। यह पॉलिसी पहले की न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी (NIP)-2012 की जगह लेगी, जो अक्टूबर 2019 में खत्म हो गई थी।

इस पॉलिसी का मुख्य मकसद घरेलू यूरिया प्रोडक्शन को बढ़ाना है और साथ ही इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र पर भारत की निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना है।

NIPU-2026 को लागू करने के पीछे क्या वजह थी?

यूरिया, यह एक तरह का फर्टिलाइज़र है जो खेती की पैदावार में अहम भूमिका निभाता है, इसका इस्तेमाल पूरे भारत में बड़े पैमाने पर होता है। पिछले कुछ सालों में घरेलू सप्लाई बढ़ने के बावजूद, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बनी हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्ट होता है।

इसलिए सरकार ने ये करने के लिए NIPU-2026 की पहल शुरू की है,

- घरेलू यूरिया उत्पादन का स्तर बढ़ाएँ
 - नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ की ओर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें
 - आयात पर निर्भरता कम करना
 - निवेश से मिलने वाले रिटर्न में पारदर्शिता बढ़ाएँ
 - भारत में फर्टिलाइज़र पर निर्भरता का लेवल बढ़ाना
 - साथ ही आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के लक्ष्यों का पालन करना
- अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ़ फर्टिलाइज़र्स से यूरिया बनाने वाले नए प्लांट लगाने के बारे में सुझाव मांगे हैं, जिससे नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत का पता चलता है।

एनआईपीयू-2026 की मुख्य विशेषताएं

NIPU-2026 पॉलिसी में कई फीचर्स हैं जो पहले के इन्वेस्टमेंट मॉडल से अलग हैं।

पॉलिसी की पहली दो खासियतें ये हैं,

नई गैस-आधारित यूरिया उत्पादन इकाइयों का गठन

पॉलिसी का जोर नई गैस-वेस्ट यूरिया प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने पर है जो एनर्जी-एफिशिएंट और एनवायरनमेंट-फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं।

फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का अलग होना।

NIPU द्वारा किया गया सबसे ज़रूरी बदलाव फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना है। इस बदलाव से ये चीज़ें हो सकती हैं:

- परियोजना अर्थशास्त्र की पारदर्शिता सुनिश्चित करना;
- लागत अनुमान में निष्पक्षता सुनिश्चित करना;
- निवेश वित्तीय योजना में सुधार;

एक तंत्र के रूप में RoE

NIPU-2026 एक स्ट्रक्चर्ड RoE मैकेनिज्म पेश करता है।

RoE के प्राप्त बैंड के अनुसार,

- न्यूनतम (फ्लोर): 12%;
- अधिकतम (छत): 16%;

जो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा भरोसा देता है और फंड्स के सही एलोकेशन की गारंटी देता है।

मुद्रा जोखिम में कमी

करेंसी में उतार-चढ़ाव से जुड़े रिस्क को कम करने के लिए, NIPU-2026 में उस समय लागू एक्सचेंज रेट को ध्यान में रखते हुए चार साल बाद फिक्स्ड कॉस्ट को भारतीय रुपये में बदलने का प्लान है।

नई पॉलिसी के फ़ायदे

सरकार को उम्मीद है कि NIPU-2026 से कई आर्थिक और स्ट्रेटेजिक फ़ायदे मिलेंगे।

देशी उत्पादन में वृद्धि

नई प्रोडक्शन यूनिट्स के शुरू होने से पूरे देश में यूरिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे खेती की यूरिया की ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी।

आयात निर्भरता कम की गई

यूरिया के लोकल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी से इम्पोर्टेड यूरिया पर निर्भरता कम होगी, जिससे देश की फर्टिलाइज़र सिक्योरिटी बेहतर होगी।

बचत

सरकार का दावा है कि बदली हुई पॉलिसी से NIPU-2026 के तहत बनाए गए हर नए प्लांट पर ₹ 250 करोड़ से ज़्यादा की बचत होने का अनुमान है, जबकि NIP-2012 के आधार पर बनाए गए प्लांट पर यह बचत नहीं होगी। निवेशकों का बढ़ा हुआ विश्वास

लागत ट्रांसपेरेंट होने के साथ-साथ गारंटीड Return on Equity और एक्सचेंज रेट के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा होने से फर्टिलाइज़र सेक्टर में निवेश आकर्षक हो सकता है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए समर्थन

इम्पोर्ट की संख्या कम करने और आत्मनिर्भरता को आसान बनाने के मकसद से घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के उपाय, देश को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के लक्ष्य को पाने में सीधा योगदान देते हैं।

पृष्ठभूमि: NIP-2012 से NIPU-2026 तक

पॉलिसी को फॉर्मल रूप से अपनाने के बाद बनने वाले सभी नए प्लांट्स को NIPU-2026 प्लान में शामिल किया जाएगा।

यूरिया सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी (NIP)-2012 लागू की गई है,

- ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ
- ब्राउनफील्ड विस्तार
- बंद संयंत्रों की बहाली
- मौजूदा यूनिट्स की क्षमता बढ़ाना

NIP-2012 की वजह से,

- छह नई यूरिया बनाने वाली यूनिट्स लगाना
- पब्लिक सेक्टर के जॉइंट वेंचर से चार नई यूनिट्स बनाना
- प्राइवेट कंपनियों द्वारा दो यूनिट्स की स्थापना

NIP-2012 के तहत इन्वेस्टमेंट विंडो अक्टूबर, 2019 में बंद हो गई और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नई पॉलिसी की ज़रूरत थी।

राष्ट्रीय समाचार

- वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के मन्त्रम इंटरनेशनल सेंटर में मन्त्रम स्मृति मंडपम का उद्घाटन किया और मन्त्रथु पद्मनाभन की मूर्ति का अनावरण किया। यह मेमोरियल मशहूर समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और नायर सर्विस सोसाइटी (NSS) के फाउंडर के सम्मान में बनाया गया है, जिन्होंने शिक्षा, बराबरी और समाज को ऊपर उठाने के लिए काम किया। वाइस प्रेसिडेंट ने न्याय, सम्मान और सबको साथ लेकर चलने के उनके विज़न की तारीफ़ करते हुए कहा कि यह जाति और इलाके की सीमाओं से ऊपर है। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम कैपेन में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने एक पौधा लगाया, पर्यावरण बचाने और कम्युनिटी सर्विस को बढ़ावा दिया।
- 14 जुलाई 2026 को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा, जिसमें नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनितेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) स्कीम के तीन साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अगुवाई में, यह पहल मैकेनाइज्ड सैनितेशन को बढ़ावा देती है, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करती है, और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और भलाई सुनिश्चित करती है। देश भर में होने वाले इवेंट्स में हेल्थ कैंप, PPE जागरूकता, मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट डेमोस्ट्रेशन, स्किल ट्रेनिंग और वेलफेयर बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होंगे। 2023-24 में शुरू की गई यह स्कीम काम की जगह की सुरक्षा में सुधार करके और सफाई कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक भलाई को बढ़ाकर एक समावेशी सैनितेशन इकोसिस्टम का समर्थन करती है।

- ONGC ने लद्दाख की पुगा वैली में अपना दूसरा जियोथर्मल कुआं सफलतापूर्वक खोदा , जो 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर 1,000 मीटर की गहराई तक पहुंचा । ONGC एनर्जी सेंटर के ज़रिए डेवलप किया गया यह प्रोजेक्ट भारत के पहले 1 MW पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट को सपोर्ट करता है। पहले कुएं की सफलता के बाद, यह इस इलाके की 24x7 क्लीन एनर्जी बनाने की जियोथर्मल क्षमता को कन्फर्म करता है । इस प्रोजेक्ट का मकसद फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम करना, दूर-दराज के हिमालयी इलाकों में एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना और 2030 तक भारत के 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी के टारगेट में योगदान देना है ।
- डिजिटल इंडिया के 11 साल पूरे होने पर , eSaras प्लेटफॉर्म ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी पहल के तौर पर सामने आया । ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ MeitY के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया , यह सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs), किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन्स (FPOs), और ग्रामीण एंटरप्रेन्योर्स को ONDC-इनेबल एप्लिकेशन्स के ज़रिए देश भर में प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करता है । 8.99 करोड़ से ज्यादा SHG मेंबर्स और 1,400+ प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हुए , यह प्लेटफॉर्म डिजिटल पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, BHASHINI के ज़रिए मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और मार्केट एक्सेस देता है । यह 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के सरकार के टारगेट में भी मदद करता है ।
- भारत टेक्स 2026 , 14-17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा , जिसमें भारत की पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन दिखाई जाएगी। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन इसे टेक्सटाइल मंत्रालय के सपोर्ट से ऑर्गनाइज़ करेगा । यह इवेंट PM नरेंद्र मोदी के 5F विज़न — फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरिन से इंस्पायर्ड है । इसमें 1,600 से ज्यादा एग्जिबिटर , 7,000 ग्लोबल खरीदार और 1.3 लाख विज़िटर के आने की उम्मीद है , जिससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल टेक्सटाइल मैनुफैक्चरिंग और सोर्सिंग हब के तौर पर भारत की जगह मज़बूत होगी ।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री (MeitY) ने CERT-In, CSIRT-Fin और SISA के साथ मिलकर भारत के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 जारी की है । रिपोर्ट में AI-पावर्ड साइबर अटैक, क्रेडेंशियल चोरी, क्लाउड एक्सप्लॉइटेशन, सोशल इंजीनियरिंग और सप्लाय चैन अटैक से बढ़ते खतरों पर रोशनी डाली गई है । यह एक साइबर फेलियर एनाटॉमी प्रेमवर्क पेश करता है और भारत के बढ़ते डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग, मज़बूत सिक्योरिटी कंट्रोल, सहयोग और प्रोएक्टिव साइबर रेजिलिएंस पर ज़ोर देते हुए 18 महीने के साइबर सिक्योरिटी रोडमैप की सिफारिश करता है।
- MeitY ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI) के साथ मिलकर , स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 2026-27 के लिए स्वयान इनिशिएटिव के तहत NIDAR 2.0 लॉन्च किया। इस कॉम्पिटिशन में ₹ 65 लाख से ज्यादा के इनाम , स्टार्टअप इनक्यूबेशन, इंटरशिप,

- क्लाउड क्रेडिट और टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। इसमें ड्रोन इनोवेशन और कंपोनेंट इनोवेशन ट्रैक शामिल हैं, जो ऑटोनामस ड्रोन, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, मेडिकल डिलीवरी, GPS-डिनाइड नेविगेशन, स्वदेशी फ्लाइट कंट्रोलर और VEGA प्रोसेसर-बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस करते हैं । यह इनिशिएटिव भारत के ड्रोन और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मज़बूत करके आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है ।
- भारत सरकार ने ऑफिशियली सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट एरिया का नाम बदलकर कर्तव्य भवन एरिया (कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स) कर दिया है । यूनिशन मिनिस्टर मनोहर लाल ने सभी मिनिस्ट्री को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सेंट्रल विस्टा शब्द का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया है । बदले गए एरिया में कर्तव्य पथ , कर्तव्य भवन , आने वाला कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट और भविष्य के सरकारी ऑफिस शामिल हैं। यह फैसला 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के बाद लिया गया है और यह सरकार के उस मकसद को दिखाता है जिसमें कॉलोनीयल-एरा के नामों को पब्लिक सर्विस, नेशनल आइडेंटिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की निशानी वाले टर्मिनोलॉजी से बदला जाएगा ।
- इंडिया पोस्ट ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में ₹ 4,009 करोड़ का अपना अब तक का सबसे अधिक राजस्व हासिल किया , जो साल-दर-साल 22% की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया की अध्यक्षता में तिमाही व्यापार समीक्षा बैठक के दौरान घोषित , यह प्रदर्शन इंडिया पोस्ट के डिजिटल रूप से सशक्त, ग्राहक-केंद्रित संगठन में परिवर्तन को दर्शाता है। नागरिक केंद्रित सेवाओं ने सबसे अधिक वृद्धि (86%) दर्ज की, उसके बाद पार्सल सेवा (50%) , मेल सेवा (42%) , और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (34%) का स्थान रहा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सर्किल के रूप में उभरे, जबकि शून्य व्यावसायिक लेनदेन में तीव्र कमी के माध्यम से परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ ।
- केंद्र सरकार संसद के मानसून सेशन में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 पेश करने की योजना बना रही है । प्रस्तावित कानून बंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश करता है, जिससे इसका अपमान या रुकावट राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान की तरह एक दंडनीय अपराध बन जाएगा । यह संशोधन “अपमान” और “रुकावट” का मतलब बताएगा , साथ ही बोलने की आज़ादी सहित संवैधानिक सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित करेगा । यह कदम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक योगदान को मान्यता देता है और राष्ट्रीय प्रतीकों और देशभक्ति के मूल्यों को बनाए रखने की कोशिशों को मज़बूत करता है।
- ICAR ने टेक्नोलॉजी , सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंस के ज़रिए भारतीय खेती को मॉडर्न बनाने के लिए विकसित कृषि विज्ञान 2047 रोडमैप पेश किया । इस प्लान का मकसद 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाना , 100 मिलियन किसानों तक पहुंचना और डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है। ICAR ने 43 नई फसल की किस्में , 17 खेती की टेक्नोलॉजी और 14 रिसर्च पब्लिकेशन भी जारी किए । यह रोडमैप AI , रोबोटिक्स , प्रिसिजन फार्मिंग और इनोवेशन के कमर्शियलाइज़ेशन को बढ़ावा देता है ताकि प्रोडक्टिविटी , किसानों की इनकम और फूड सिक्योरिटी बढ़े , और विकसित भारत 2047 को सपोर्ट मिले ।

- इंडियन रेलवे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जींद-सोनीपत रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन शुरू करेगा। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) फ्यूल सेल से चलने वाली यह ट्रेन सिर्फ पानी की भाप और गर्मी छोड़ती है। लगभग 2,600 यात्रियों के लिए डिज़ाइन की गई इस ट्रेन में जींद में 3,000 kg हाइड्रोजन रीफ्यूलिंग की सुविधा भी है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया यह प्रोजेक्ट नेट जीरो लक्ष्यों को सपोर्ट करता है और क्लीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देता है।
- सरकार ने गोइंग ग्लोबल: ए प्रैक्टिकल गाइड फॉर इंडियन MSMEs लॉन्च किया है, जिसे CTIL-IIFT और CII ने तैयार किया है, ताकि MSMEs को इंटरनेशनल मार्केट में आने में मदद मिल सके। इस गाइडबुक में एक्सपोर्ट प्लानिंग, ट्रेड इंटेलिजेंस, मार्केट एक्सेस, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTAs), रूल्स ऑफ ओरिजिन और ट्रेड रेमेडीज शामिल हैं। इसका मकसद ट्रेड में रुकावटों को कम करके और एक्सपोर्ट अवैरनेस को बेहतर बनाकर MSME एक्सपोर्ट को मजबूत करना है।
- नीति आयोग ने आठ प्रमुख स्तंभों में 84 संकेतकों का उपयोग करके सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निवेश तत्परता का आकलन करने के लिए पहला निवेश मित्रता सूचकांक (IFI) जारी किया। एक बेंचमार्किंग टूल के रूप में डिज़ाइन किया गया, यह सूचकांक प्रतिस्पर्धा पैदा करने की बजाय निवेश पारिस्थितिकी तंत्रों को बेहतर बनाने के लिए सुधारों को प्रोत्साहित करता है। गुजरात 56.6 स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्य के रूप में उभरा, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा का स्थान रहा, जबकि गोवा केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सबसे आगे रहा। चूंकि किसी भी राज्य ने 60 का आंकड़ा पार नहीं किया, इसलिए रिपोर्ट में विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए शासन, बुनियादी ढांचे, कारोबारी माहौल और नियामक सुधारों में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कंडक्ट (NCRBC) 2026 नई दिल्ली में हुआ, जिसकी थीम थी "विकसित भारत के लिए ESG-लेड ट्रांसफॉर्मेशन।" कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (IICA) ने इसे ऑर्गनाइज़ किया। इस कॉन्फ्रेंस में भारत की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ESG) प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करने पर फोकस किया गया। एक्सपर्ट्स ने सस्टेनेबिलिटी और इनक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपेरेंट ESG रिपोर्टिंग, AI-इनेबल्ड रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल सप्लाय चैन और ग्रीनवाशिंग को रोकने पर ज़ोर दिया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PGIMER चंडीगढ़ में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर का उद्घाटन किया और PM-ABHIM के तहत 150 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की नींव रखी। ये प्रोजेक्ट्स मैटरनल केयर, पीडियाट्रिक सर्विसेज़, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने AIIMS के विस्तार, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ई-संजीवनी कंसल्टेशन और नए मेडिकल कॉलेज जैसी उपलब्धियों पर भी ज़ोर दिया।
- लखनऊ के कुकरेल रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में अपनी पहली अर्बन नाइट सफ़ारी बनाने की मंजूरी मिल गई है। 855 एकड़ में फैले इस ₹ 1,510 करोड़ के प्रोजेक्ट में नेचुरल वाइल्डलाइफ़ के बाड़े, एक डे जू, इको-फ़्रेडली

- सफ़ारी गाड़ियाँ, जंगल के रास्ते और एजुकेशनल सेंटर शामिल होंगे। सफ़ारी में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, तेंदुए, लकड़बग्घे, उड़ने वाली गिलहरी और घड़ियाल जैसी प्रजातियाँ रहेंगी, जिससे वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन, इको-टूरिज़्म और एनवायरनमेंटल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा।
- लद्दाख की पुगा वैली में अपना पहला डीप जियोथर्मल वेल चालू किया है, जिसमें ONGC एनर्जी सेंटर ने 1,000 मीटर तक दो कुएं खोदे हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद 1 MW के पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट को सपोर्ट करना है, जिसका रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर 135°C है, जो मजबूत जियोथर्मल पोटेंशियल दिखाता है। यह पहल रिन्यूएबल एनर्जी, 24x7 क्लीन पावर और सस्टेनेबल एनर्जी जेनरेशन को बढ़ावा देती है।
- PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। राज्य में 2.28 GW कैपेसिटी के साथ 6.74 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशन हुए, जो गुजरात से पीछे है। इस प्रोग्राम ने क्लीन एनर्जी अपनाने को बढ़ावा दिया है, बिजली की लागत कम की है, और सोलर सेक्टर में लगभग 85,000 नौकरियां पैदा की हैं।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2026 को सुथुत जयंती के मौके पर नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद (AIIA) में तीन दिन के इंटरनेशनल सेमिनार सौथुतम 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट के MRI सेक्शन का भी उद्घाटन किया और आचार्य सुथुत को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें सर्जरी का जनक माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी और सर्जिकल साइंस में उनके अहम योगदान पर रोशनी डालते हुए, उन्होंने आयुर्वेद को मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च और सबूतों पर आधारित दवा के साथ जोड़ने पर ज़ोर दिया। यह सेमिनार मॉडर्न हेल्थकेयर में आयुर्वेद की भूमिका को मजबूत करते हुए आयुर्वेदिक रिसर्च में इनोवेशन, नैतिकता और ग्लोबल सहयोग को बढ़ावा देता है।
- भारी उद्योग मंत्रालय ने ₹ 18,100 करोड़ की PLI स्कीम के तहत 10 GWh एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी बनाने के लिए बोलियां मंगाई हैं। इस आखिरी एलोकेशन फेज़ का मकसद 50 GWh घरेलू बैटरी कैपेसिटी बनाने का टारगेट पूरा करना है, जिसमें से लगभग 40 GWh पहले ही अलॉट हो चुकी हैं। 2021 में लॉन्च हुई यह स्कीम इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए ज़रूरी अगली पीढ़ी की बैटरी को सपोर्ट करती है। इसका मकसद इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना, घरेलू मैनुफैक्चरिंग को मजबूत करना, एनर्जी सिक्योरिटी में सुधार करना और एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन को तेज़ करना है।
- इंडियन रेलवे ने रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल शुरू की, जिसमें लॉजिस्टिक्स को मॉडर्न बनाने और माल ढुलाई की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए आठ बड़े माल ढुलाई सुधार पेश किए गए। इसके साथ ही, प्लान किए गए 52 सुधारों में से 17 पूरे हो गए हैं। इन सुधारों में कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए आसान लाइसेंसिंग, कंटेनर वाले कार्गो मूवमेंट का विस्तार, माल ढुलाई के टैरिफ को सही करना और डिजिटाइज़्ड ज़मीन अधिग्रहण के लिए रेल भूमि पोर्टल शामिल हैं। इन उपायों का मकसद लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देना, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में सुधार करना और रेल ट्रांसपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाते हुए भारत के माल ढुलाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।

- यूनियन कैबिनेट ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ₹ 1.27 लाख करोड़ के खर्च के साथ Semicon 2.0 को मंजूरी दी है। Semicon 1.0 पर आधारित यह प्रोग्राम चिप डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, रिसर्च और वर्कफ़ोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करता है। सेमीकंडक्टर AI, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, टेलीकॉम, हेल्थकेयर और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस पहल का मकसद इम्पोर्टेड चिप्स पर निर्भरता कम करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना और भारत को एक भरोसेमंद ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करना है, साथ ही लंबे समय तक टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता को सपोर्ट करना है।
- यूनियन कैबिनेट ने वाराणसी डीकंजेशन प्लान के तहत ₹ 25,400 करोड़ से ज़्यादा के दो बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स में वरुणा और गंगा नदियों के किनारे एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं, जिससे यात्रा का समय कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़ने वाला 910 मीटर का केबल-स्टेड ब्रिज और 1.32 km का ट्रैवलेटर वाला फुट ओवरब्रिज भी प्लान किया गया है। NHAI द्वारा हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत लागू किए गए इन प्रोजेक्ट्स का मकसद भीड़भाड़ कम करना, टूरिज्म बढ़ाना, शहरी मोबिलिटी में सुधार करना और वाराणसी के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।
- केंद्र सरकार मानसून सेशन के दौरान राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 पेश करेगी। यह बिल बंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देता है, जिससे इसका अपमान या रुकावट डालना राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान की तरह सज़ा का हकदार होगा। यह संविधान के तहत बोलने की आज़ादी की रक्षा करते हुए खास शब्दों को बताता है। यह कदम भारत के आज़ादी के आंदोलन में बंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को पहचान देता है और इसका मकसद राष्ट्रीय प्रतीकों, देशभक्ति के मूल्यों और राष्ट्रीय गीत के सम्मान को बनाए रखना है।
- ICAR ने AI, रोबोटिक्स, प्रिसिजन फार्मिंग और क्लाइमेट-स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को मॉडर्न बनाने के लिए विकसित कृषि विज्ञान 2047 लॉन्च किया है। रोडमैप का टारगेट 100 क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाना है, जो 100 मिलियन किसानों तक पहुंचेगा, और इसमें 43 फसल की किस्में, 17 खेती की टेक्नोलॉजी और 14 रिसर्च पब्लिकेशन शामिल हैं। यह डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म, इनोवेशन कमर्शियलाइजेशन, किसानों की बेहतर इनकम, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देता है। यह पहल टेक्नोलॉजी से चलने वाला और क्लाइमेट-रेसिलिएंट खेती का इकोसिस्टम बनाकर विकसित भारत 2047 के विज्ञान को सपोर्ट करती है।
- इंडियन रेलवे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हरियाणा में जींद-सोनीपत रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन शुरू करेगा। PEM फ्यूल सेल से चलने वाली यह ट्रेन सिर्फ़ पानी की भाप और गर्मी छोड़ती है, जिससे यह इको-फ्रेंडली है। इसमें 2,600 यात्री बैठ सकते हैं, इसमें एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम हैं, और इसमें 3,000 kg हाइड्रोजन रीफ्यूलिंग की सुविधा भी है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी का

इस्तेमाल करके बनाया गया यह प्रोजेक्ट नेट ज़ीरो, क्लीन मोबिलिटी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और हाइड्रोजन से चलने वाले रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेशन को सपोर्ट करता है।

- सरकार ने MSME एक्सपोर्ट को मजबूत करने के लिए CTIL-IIFT और CII की बनाई 'गोइंग ग्लोबल: ए प्रैक्टिकल गाइड फॉर इंडियन MSMEs' नाम की एक किताब लॉन्च की है। इस गाइड में एक्सपोर्ट प्लानिंग, ट्रेड इंटेलिजेंस, मार्केट एक्सेस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTAs), रूल्स ऑफ ओरिजिन, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड और ग्लोबल कम्प्लायंस के बारे में बताया गया है। यह रेगुलेटरी चुनौतियों को सुलझाता है, एक्सपोर्ट अवेयरनेस को बेहतर बनाता है, ट्रेड में रुकावटों को कम करता है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है। इस पहल का मकसद भारतीय MSMEs को इंटरनेशनल मार्केट में फैलने में मदद करना और भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ में अहम योगदान देना है।

राज्य समाचार

- अहमदाबाद ने सिर्फ़ एक घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी प्लांटेशन ड्राइव बन गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) ने भदज में इसे ऑर्गनाइज़ किया था। इस कैपेन में 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स शामिल थे, जिनमें स्टूडेंट्स, NCC कैडेट्स, अधिकारी, पुलिस वाले और आम लोग शामिल थे। 91,006 स्क्वायर मीटर में फैले इस प्लांटेशन में मियावाकी तरीके का इस्तेमाल करके 35 देसी पेड़ों की किस्में शामिल थीं, जिससे तेज़ी से घने जंगल बनते हैं। यह पहल पिछले ग्लोबल रिकॉर्ड को पार करते हुए ग्रीन कवर, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंस और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन को बढ़ाती है।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, खेला होवे दिवस की जगह 16 अगस्त का नाम बदलकर आयुष्मान दिवस कर दिया है। मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी द्वारा घोषित इस कार्यक्रम में जागरूकता अभियान, आउटरीच प्रोग्राम और योग्य परिवारों के लिए योजना के तहत ₹ 5 लाख सालाना कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रकाश डालने वाले पब्लिक इवेंट होंगे। इससे पहले, इस दिन खेला होवे दिवस के तहत खेलों को बढ़ावा दिया गया था। यह बदलाव हेल्थकेयर जागरूकता, सस्ते इलाज और मेडिकल सेवाओं तक बेहतर पहुंच पर राज्य के नए फोकस को दिखाता है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने आबादी की बैलेंस्ड ग्रोथ को बढ़ावा देने और भविष्य की डेमोग्राफिक चुनौतियों से निपटने के लिए पिಲ್ಲाले संपदा (बच्चे ही पैसा हैं) पहल शुरू की। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटती फर्टिलिटी रेट के बीच सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स के महत्व पर ज़ोर दिया। यह पहल मैटरनल हेल्थकेयर, बच्चों के न्यूट्रिशन, आंगनवाड़ी को मजबूत बनाने, महिलाओं के एम्पावरमेंट, वर्कप्लेस पर बच्चों की देखभाल और तल्लिकी वंदनम स्कीम के ज़रिए एजुकेशन सपोर्ट पर फोकस करती है, जिसमें हर बच्चे को ₹ 15,000 दिए जाते हैं। स्वर्ण आंध्र 2047 विज़न से जुड़ा, इसका मकसद भविष्य में एक हेल्दी, पढ़ा-लिखा और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाना है।



ALL EXAMS, **ONE** SUBSCRIPTION

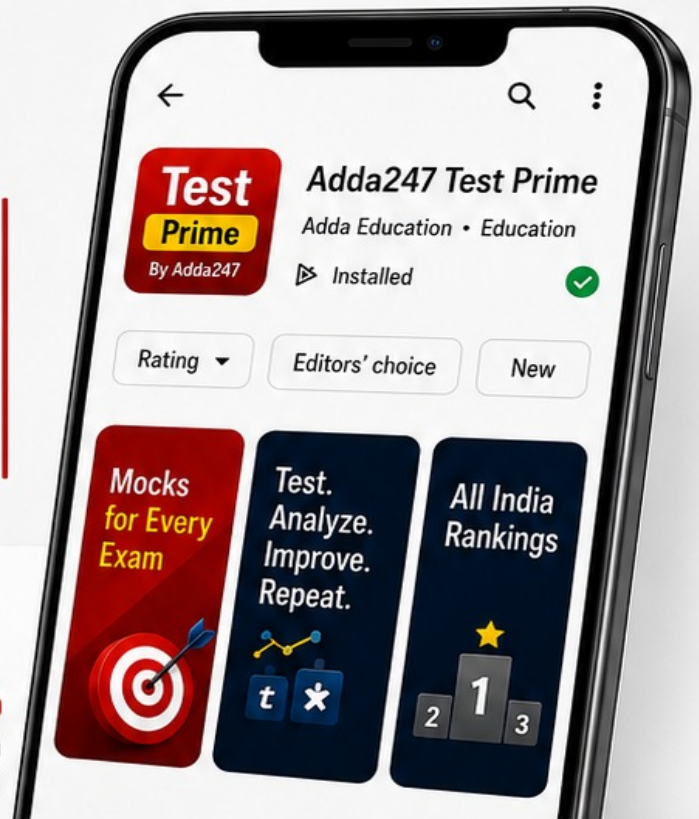


Test. Analyze. Improve. Repeat.



*Don't just
prepare.
Perform.*

Test Prime – built only
for mock tests.



1,50,000+
Mock Tests



25,000+
Previous Year
Papers



800+
Exam
Covered



500%
Refund on
Selection



5 lakh+
Free Quizzes



Daily
Free PDFs



Top Alerts
Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- ✓ Multilingual
- ✓ Detailed Solution
- ✓ Strong and Weak Areas
- ✓ All India Rankings



Safe & Reliable



Trusted by
Lakhs of Aspirants

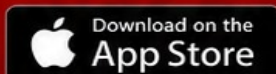
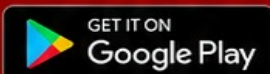


Your Success,
Our Mission



**DOWNLOAD
TEST PRIME**

Your Success Partner!



- स्पेन के सबमर ग्रुप ने MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 के दौरान मध्य प्रदेश में \$2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट में एक सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी और एक 1-गीगाबाइट डेटा सेंटर शामिल है, जिससे लगभग 5,000 डायरेक्ट जॉब्स बनेंगी। अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जल्दी ज़मीन मिलने से, यह इन्वेस्टमेंट भारत के सेमीकंडक्टर मिशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट और एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी मैनुफैक्चरिंग को मज़बूत करेगा। यह पहल मध्य प्रदेश को हाई-टेक मैनुफैक्चरिंग के लिए एक अहम जगह के तौर पर उभरने में मदद करती है और भारत के ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने के सपनों को सपोर्ट करती है।
- तमिलनाडु ने कम्युनिटी-बेस्ड सर्विलांस के ज़रिए शहरी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए चेन्नई में सिक्योर आवर सिटी (SOC) कैपेन के सभी पाँच फेज़ सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। सिक्योरकैम इंडिया की लीडरशिप में, इस पहल ने रिहायशी इलाकों, स्कूलों और पब्लिक जगहों पर मुफ्त CCTV सिस्टम लगाए। SM नगर में 800 से ज़्यादा घरों और कर्पगाम एवेन्यू में 600 से ज़्यादा घरों को इस प्रोग्राम से फ़ायदा हुआ। कई मोहल्लों को कवर करते हुए, इस कैपेन का मकसद टेक्नोलॉजी से चलने वाली पब्लिक सुरक्षा पहलों के ज़रिए महिलाओं की सुरक्षा, क्राइम की रोकथाम, इमरजेंसी में मदद, कम्युनिटी की भागीदारी और कमज़ोर ग्रुप्स की सुरक्षा को बढ़ाना है।
- उत्तराखंड ने हल्द्वानी के फॉरिस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में अपनी पहली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (GI) प्रोडक्ट्स गैलरी का उद्घाटन किया। गैलरी में 30 से ज़्यादा GI-टैग वाले प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं, जिनमें मुनस्यारी व्हाइट राजमा, बेरीनाग चाय, ऐपण आर्ट, रिंगाल बैम्बू क्राफ्ट, टम्टा कॉपरवेयर और बुरांश शरबत शामिल हैं। यह पहल असली क्षेत्रीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देती है, पारंपरिक ज्ञान को बचाती है और किसानों और कारीगरों के लिए बाज़ार के मौके बढ़ाती है। उत्तराखंड ने पहले 2023 में एक ही दिन में 18 GI टैग पाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, जिससे उसकी सांस्कृतिक और खेती की पहचान मज़बूत हुई थी।
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सभी सात जिलों में ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (AHDCs) बनाएगा, जो लेह और कारगिल से आगे तक फैलेगी। ये काउंसिल शिक्षा, हेल्थकेयर, टूरिज्म, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग की देखरेख करेंगी। लद्दाख ने एक केंद्र शासित प्रदेश-लेवल कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क का भी प्रस्ताव रखा, जो शायद एक कस्टमाइज्ड आर्टिकल 371 अरेंजमेंट के तहत होगा। इस पहल का मकसद केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने के बाद जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी, डीसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को मज़बूत करना है।
- बिहार सरकार ने टूरिज्म कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026 शुरू की है। सरकार हर टिकट पर ₹ 15,422 तक की सब्सिडी देगी, जिससे हेलीकॉप्टर का सफर सस्ता हो जाएगा। सर्विस 18 जुलाई 2026 से शुरू होगी, जो पटना को राजगीर, वाल्मीकिनगर और मां

- मुंडेश्वरी मंदिर (कैमूर) से जोड़ेगी। टिकट की कीमत ₹ 2,100 से शुरू होती है। इस पहल का मकसद धार्मिक, हेरिटेज, इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना, रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और बिहार के कल्चरल और नेचुरल अट्रैक्शन को बढ़ावा देना है।
- GI रजिस्ट्री ने गुजरात के मेहसाणा ज़िले के ऊंझा जीरा (जीरा) और ऊंझा सौंफ (सौंफ) को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) का स्टेटस दिया है। यह पहचान इन मसालों को नकल से बचाती है और साथ ही ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और किसानों की इनकम को बढ़ाती है। यह सर्टिफिकेशन ऊंझा APMC, गुजरात डिपार्टमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर, SDAU और EDII की कोशिशों से मिला है। गुजरात, जो भारत का सबसे बड़ा जीरा प्रोड्यूसर है, ने GI-सर्टिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अपने पोर्टफोलियो को और मज़बूत किया है, जिससे मसालों की सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिला है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत में 2026 की पहली छमाही के दौरान ₹ 10,178 करोड़ से ज़्यादा के नुकसान वाली 12.7 लाख से ज़्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की गईं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिकायतें (1.85 लाख) दर्ज की गईं, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और बिहार का स्थान रहा। बड़े स्केम में डिजिटल गिरफ्तारी, नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम, OTP फ्रॉड, UPI फ्रॉड, नकली कस्टमर केयर, जॉब स्कैम, कूरियर फ्रॉड और सोशल मीडिया पर किसी और की नकल करना शामिल थे। नागरिकों को टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने, बैंकिंग क्रेडेंशियल शेयर करने से बचने और हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट करने की सलाह दी गई।
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में Google I/O Connect India 2026 के दौरान भारत की पहली सरकारी मदद वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की घोषणा की। यह यूनिवर्सिटी AI एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री कोलेबोरेशन को बढ़ावा देगी और साथ ही उभरते AI-ड्रिवन सेक्टर के लिए प्रोफेशनल्स को तैयार करेगी। राज्य स्टार्टअप्स, इनक्यूबेशन और रिसर्च पार्टनरशिप को सपोर्ट करने के लिए एक AI हब भी बनाएगा। यह पहल कर्नाटक के AI-नेटिव राज्य बनने के विज़न से मेल खाती है, जिसमें AI को गवर्नेंस, हेल्थकेयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और पब्लिक सर्विसेज़ में इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही जिम्मेदार AI डेवलपमेंट पर Google के साथ कोलेबोरेशन को मज़बूत किया जाएगा।
- इंडोनेशिया के अपने ऑफिशियल दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो और स्पीकर पुआन महारानी को पारंपरिक भारतीय तोहफ़े दिए। तोहफ़ों में असम की मनोहारी गोल्ड टी, उत्तराखंड की ऐपन आर्ट, कश्मीरी पपीयर-मैचे बाउल, रेपौसे सिल्वर प्लेट और ओडिशा इकत सिल्क शामिल थे। इन चीज़ों में भारत की चाय की विरासत, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम की परंपराएं और सांस्कृतिक विविधता दिखाई गई। इस पहल ने भारत-इंडोनेशिया कल्चरल डिप्लोमेसी को मज़बूत किया, भारतीय कारीगरों को बढ़ावा दिया और सदियों पुरानी कारीगरी को दिखाया, साथ ही दोनों देशों के बीच करीबी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मज़बूत किया।

- ऑस्ट्रेलिया दौर के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई नेताओं को पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कलाकृतियां तोहफे में दीं। इस कलेक्शन में ढोकरा बोट स्कल्पचर, प्रीमियम इंडियन कॉफी बॉक्स, कॉलोनियल कज़िन्स विनाइल रिकॉर्ड, कश्मीरी कढ़ाई वाला स्टोल, मधुबनी पेंटिंग, मार्बल इनले बॉक्स और राजस्थानी लकड़ी के हाथी की मूर्ति शामिल थी। ये तोहफे भारत की आदिवासी कला, कॉफी विरासत, संगीत, कढ़ाई, पेंटिंग और हस्तशिल्प परंपराओं को दिखाते थे। इस पहल ने भारतीय कारीगरों, क्षेत्रीय कारीगरी और सांस्कृतिक डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया, साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी रिश्ते और लोगों के बीच जुड़ाव को भी मजबूत किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल दौर के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और विपक्ष के नेता क्रिस हिपकिंस को पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प तोहफे में दिए। तोहफों में ढोकरा ट्री ऑफ़ लाइफ़ की मूर्ति, पारंपरिक उत्तराखंडी टोपी, साइन की हुई हाँकी स्टिक और लखनऊ ज़री ज़रदोज़ी की दीवार पर लटकने वाली चीज़ें शामिल थीं। इनमें आदिवासी मेटल आर्ट, हिमालयी परंपराएं, खेल की उपलब्धियां और भारत की समृद्ध कढ़ाई की विरासत दिखाई गई। इस पहल ने भारत की अलग-अलग तरह की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया, स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा दिया और लोगों के बीच अच्छे जुड़ाव के ज़रिए भारत-न्यूजीलैंड की सांस्कृतिक डिप्लोमेसी को मजबूत किया।
- भारत और मालदीव ने 29 जून से 7 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए बातचीत का पहला राउंड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वर्चुअल चर्चा में आठ बातचीत ट्रैक शामिल थे, जो मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, डिजिटल पेमेंट, MSMEs और स्टार्टअप सहयोग पर फोकस करते थे। दोनों देश बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी (BIT) पर बातचीत में तेज़ी लाने पर भी सहमत हुए। यह बातचीत डिप्लोमैटिक संबंधों की 60वीं सालगिरह के मौके पर हुई, जबकि बाइलेटरल ट्रेड 2025-26 में USD 771.76 मिलियन तक पहुंच गया, जो बढ़ते आर्थिक सहयोग को दिखाता है।
- भारत ने फिलिस्तीन की पूरी UN मेंबरशिप के लिए अपना सपोर्ट दोहराया और ब्रुसेल्स और न्यूयॉर्क में मीटिंग के दौरान टू-स्टेट सॉल्यूशन के लिए अपना कमिटमेंट दोहराया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई मानवीय मदद की घोषणा की, जिसमें एक स्पेशलिटी मेडिकल हॉस्पिटल, आर्टिफिशियल लिंब सेंटर और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शामिल हैं। भारत ने UNRWA को भी लगातार सपोर्ट देने का वादा किया, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, हेल्थकेयर और राहत सर्विस देता है। यह घोषणा पश्चिम एशिया में शांति, मानवीय मदद और डेवलपमेंट में सहयोग के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे कमिटमेंट को दिखाती है।
- यूक्रेन और नौ यूरोपियन देशों ने पेरिस में अपनी पहली मीटिंग के दौरान एक नया एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कोएलिशन लॉन्च किया। इस कोएलिशन में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। इसका मकसद कॉमन मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना, डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन को मजबूत करना और बाहरी सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम करना है। एक बड़ी पहल, प्रोजेक्ट फ्रेया, यूक्रेन के बैटलफील्ड एक्सपीरियंस को यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर एडवांस्ड मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम डेवलप करेगी, जिससे बढ़ते मिसाइल खतरों के बीच रीजनल सिक्योरिटी बढ़ेगी।
- भारत अपनी BRICS चैयरपर्सनशिप में 15-16 जुलाई 2026 को हैदराबाद में 12वीं BRICS लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट कर रहा है। यूनिन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में, मीटिंग सोशल सिक्योरिटी, लेबर मार्केट फॉर्मलाइजेशन, महिला वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, स्किल डेवलपमेंट और वर्कर वेलफेयर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगी। "बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी (BRICS)" थीम पर आधारित, मीटिंग का मकसद BRICS देशों के बीच लेबर कोऑपरेशन को मजबूत करना और एक रेजिलिएंट फ्यूचर वर्कफोर्स बनाना है।
- इंडिया-यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ, जिसका टारगेट 2030 तक USD 100 बिलियन का बाइलेटरल ट्रेड है। यह एग्रीमेंट टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, ज्वेलरी और प्लास्टिक जैसे इंडियन एक्सपोर्ट के लिए ज़ीरो-ड्यूटी एक्सेस देता है, साथ ही सेफगाड्स के ज़रिए इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बचाता है। CETA के साथ, डबल कंट्रीव्यूथन कन्वेंशन (DCC) से 75,000 से ज़्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स को डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीव्यूथन को रोककर फ़ायदा होगा, जिससे सालाना USD 600 मिलियन से ज़्यादा की बचत होगी और बाइलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन मजबूत होगा।
- कर्नाटक अपार्टमेंट (ओनरशिप और मैनेजमेंट) बिल, 2025 के ड्राफ्ट का मकसद अपार्टमेंट गवर्नेंस को मॉडर्न बनाना और इसे RERA के साथ अलाइन करना है। इसमें ज़मीन और कॉमन एरिया की जॉइंट ओनरशिप का प्रस्ताव है, अपार्टमेंट ओनर्स काउंसिल बनाई गई हैं, और एक रीडेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसके लिए 75% मालिकों की मंजूरी ज़रूरी है। बिलिंग्स को हर पाँच साल में स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफ़िकेट लेना होगा। इन सुधारों का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, झगड़े कम करना और रहने वालों के अधिकारों को मजबूत करना है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने वोकेशनल ट्रेनिंग को मजबूत करने और रोज़गार के मौकों को बेहतर बनाने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी लॉन्च किए। कौशल सेतु ट्रेनिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन को डिजिटाइज़ करता है, जबकि कौशल सारथी स्टूडेंट्स को कोर्स, स्किल सेंटर और नौकरियों से जोड़ता है। UPSDM ने युवाओं की रोज़गार की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए AI, रोबोटिक्स और टेक्स्टाइल में ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप भी की।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने एक जैसा लैंड-यूज़ और अर्बन प्लानिंग फ्रेमवर्क बनाने के लिए कॉमन ज़ोनिंग रेगुलेशन (CZR), 2026 को नोटिफ़ाई किया है। इन रेगुलेशन में लैंड-यूज़ कैटेगरी को 16 से घटाकर 9 कर दिया गया है और नेगेटिव-लिस्ट ज़ोनिंग अप्रोच शुरू किया गया है, जिससे बिज़नेस करने में आसानी, ट्रांसपेरेंट लैंड-यूज़ मैनेजमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में सुधार होगा।

- महाराष्ट्र ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को तेजी से लागू किया है। ₹ 48 करोड़ का यह प्रोजेक्ट "वन नेशन, वन एप्लीकेशन" के विज़न के तहत मुंबई और नागपुर में कानूनी कार्रवाई को डिजिटल करेगा। इसका मकसद पेपरलेस गवर्नेंस, कानूनी कुशलता, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाना है।
- रेलवे सेफ्टी कमिश्नर से सेफ्टी क्लियरेंस मिलने के बाद कोलकाता मेट्रो अपनी ग्रीन और पर्पल लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। ग्रीन लाइन में हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो टनल शामिल है। कम्युनिकेशन-वेस्ड ट्रेन कंट्रोल (CBTC) और ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन-4 (GoA-4) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ट्रेनें सेंट्रलाइज़्ड मॉनिटरिंग के तहत बिना ऑनबोर्ड ड्राइवर के चलेंगी। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और स्मार्ट सिग्नलिंग जैसे एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम सुरक्षित ऑपरेशन पक्का करेंगे, जिससे कोलकाता ऑटोमेटेड मेट्रो ट्रांसपोर्ट में भारत के लीडिंग शहरों में से एक बन जाएगा।
- कर्नाटक अपार्टमेंट (ओनरशिप और मैनेजमेंट) बिल, 2025 का ड्राफ्ट अपार्टमेंट गवर्नेंस को RERA के साथ जोड़ता है। इसमें ज़मीन और कॉमन एरिया की जॉइंट ओनरशिप, अपार्टमेंट ओनर्स काउंसिल, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी डेफिनिशन, 75% ओनर की सहमति से रीडेवलपमेंट, और पुरानी बिल्डिंग्स के लिए हर पांच साल में ज़रूरी स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट का प्रस्ताव है। आठ या उससे ज़्यादा यूनिट वाले कॉम्प्लेक्स पर लागू होने वाले इस बिल का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, रहने वालों के अधिकारों की रक्षा करना, झगड़े कम करना और सुरक्षित शहरी घर पक्का करना है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने वोक्शनल ट्रेनिंग और रोज़गार को बेहतर बनाने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी लॉन्च किए। कौशल सेतु ट्रेनिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज़ करता है, जबकि कौशल सारथी स्टूडेंट्स को कोर्स, स्किल सेंटर्स और नौकरियों से जोड़ता है। UPSDM ने AI, रोबोटिक्स और टेक्सटाइल्स में ट्रेनिंग के लिए पार्टनरशिप साइन की। यह पहल इंडस्ट्री-एकेडेमिया के बीच सहयोग को मज़बूत करती है, इंडस्ट्री के लिए तैयार स्किल्स बनाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है, और लंबे समय के आर्थिक विकास के लिए युवाओं की रोज़गार की क्षमता को बढ़ाती है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

- 14 देशों ने साउथ चाइना सी आर्बिट्रेशन के फैसले को फिर से कन्फर्म किया (90 शब्द)
- अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस समेत चौदह देशों ने UNCLOS के तहत 2016 के साउथ चाइना सी आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को फिर से कन्फर्म किया और चीन के नाइन-डैश लाइन के दावों को खारिज कर दिया। फैसले की 10वीं सालगिरह पर जारी जॉइंट स्टेटमेंट में ट्रिब्यूनल के फैसले को आखिरी और कानूनी तौर पर मानने वाला बताया गया। देशों ने बढ़ते तनाव, ज़बरदस्ती की समुद्री गतिविधियों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरों पर चिंता जताई। उन्होंने स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण साउथ चाइना सी में नेविगेशन की आज़ादी, शांतिपूर्ण विवाद समाधान, इंटरनेशनल कानून और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के लिए अपने सपोर्ट को फिर से कन्फर्म किया।

- भारत ने इंडिया-ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) के तहत टैरिफ रेट कोटा (TRQ) एलोकेशन प्रोसेस की घोषणा की, जो 1 जून 2026 से लागू होगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT) द्वारा जारी यह नोटिफिकेशन, खजूर, मार्बल, एल्युमीनियम प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल, कॉपर बेल्ट वायर और LDPE जैसे खास इंपोर्ट पर रियायती टैरिफ की अनुमति देता है। योग्य इंपोर्टर्स को ओमान से एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन लेना होगा। TRQ मैकेनिज्म का मकसद घरेलू इंडस्ट्री के हितों को बैलेंस करते हुए बाइलेटरल ट्रेड को आसान बनाना है।
- यूनाइटेड नेशंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अपनी पहली साइंटिफिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सरकारों से ग्लोबल AI गवर्नेंस को मज़बूत करने की अपील की गई। AI पर इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में AI के मौकों, जोखिमों और अमेरिका और चीन के बढ़ते कंप्यूटिंग डिवाइड पर रोशनी डाली गई है। इसमें AI एप्लीकेशन, सुरक्षा, मानवाधिकार, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, गवर्नेंस और आर्थिक असर शामिल हैं। भारत के लिए, रिपोर्ट में इंडिया AI मिशन के ज़रिए घरेलू कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है ताकि टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस सुनिश्चित हो सके।
- ज़ांज़ीबार के प्रेसिडेंट डॉ. हुसैन अली म्विनी ने एजुकेशन, हेल्थकेयर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन को मज़बूत करने के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने IIT मद्रास के 63वें कॉन्वोकेशन में हिस्सा लिया, जिसमें IIT मद्रास ज़ांज़ीबार कैम्पस (2023) की सफलता पर ज़ोर दिया गया। इस दौरे ने इंडिया-तंजानिया रिश्तों और साउथ-साउथ कोऑपरेशन में इंडिया के रोल को मज़बूत किया।
- एंडी बर्नहैम को UK लेबर पार्टी का नया लीडर चुना गया है और उम्मीद है कि वे सर कीर स्टारमर की जगह यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उन्होंने जनता का भरोसा वापस लाने, पब्लिक सर्विसेज़ को मज़बूत करने, रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, लोकल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी बढ़ाने और सबको साथ लेकर चलने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने का वादा किया।
- राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की अगुवाई में सरकार में फेरबदल के बाद सेरही कोरेत्स्की को यूक्रेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। पहले नैफ्टोगाज़ के CEO रहे, वे चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान एनर्जी सिक्योरिटी, आर्थिक स्थिरता, पब्लिक सर्विसेज़ और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर ध्यान देंगे।
- भारत ने 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 5वीं BIMSTEC नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स मीटिंग होस्ट की, जिसमें सभी सात सदस्य देशों के सीनियर अधिकारी एक साथ आए। बातचीत साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद, ट्रांसनेशनल क्राइम, ट्रैफिकिंग, सैटेलाइट कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर फोकस रही। मीटिंग में रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन और उभरते खतरों के खिलाफ कलेक्टिव एक्शन के लिए भारत के कमिटमेंट पर ज़ोर दिया गया। इसने इस इलाके में शांति, स्टेबिलिटी और सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच कोऑपरेशन को भी मज़बूत किया।

- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC49) के 49वें सेशन में सात इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स को अपनाने में अहम भूमिका निभाई। FSSAI के CEO राजित पुन्हानी की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन ने सूखे धानिये के बीज और ताजे करी पत्तों पर स्टैंडर्ड्स की अध्यक्षता की, जबकि वनीला, इलायची और फूड-प्रोसेसिंग वॉटर सेफ्टी पर गाइडलाइंस की को-चेयरिंग की। भारत ने काजू की गुठली के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का भी प्रस्ताव रखा, जिससे फूड सेफ्टी, इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल स्टैंडर्ड-सेटिंग में उसकी लीडरशिप मजबूत हुई।
- ज़ाज़ीबार के प्रेसिडेंट डॉ. हुसैन अली म्विनी एजुकेशन, हेल्थकेयर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए इंडिया आए। उन्होंने 63वें IIT मद्रास कॉन्वोकेशन में हिस्सा लिया और IIT मद्रास ज़ाज़ीबार कैम्पस (2023) की सफलता पर ज़ोर दिया। इस विज़िट ने इंडिया-तंजानिया स्ट्रेटिजिक रिश्तों को मजबूत किया, साउथ-साउथ कोऑपरेशन, एजुकेशनल कोलेबोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया, साथ ही दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक, कल्चरल और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट को भी बढ़ाया।

बैंकिंग/अर्थव्यवस्था/व्यापार समाचार

- जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने अपने प्रस्तावित IPO से पहले, किरण थॉमस की जगह पंकज पवार को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। पवार, जो 2000 से रिलायंस में हैं और रिलायंस जियो इंफोकॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके पास टेलीकॉम का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। लीडरशिप में बदलाव की जानकारी SEBI के पास फाइल किए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) में दी गई है। कंपनी का प्लान लगभग USD 4 बिलियन (₹ 37,700 करोड़) जुटाने का है, जो शायद इसे भारत का सबसे बड़ा IPO बना देगा।
- पॉलिसीबाजार ने पूरे भारत में हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को अपना इंश्योरेंस अवेयरनेस एंबेसडर बनाया है। यह कैम्पेन IRDAI के 2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस विज्ञान को सपोर्ट करता है और परिवारों को फाइनेंशियल सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। 'परिवार सबसे पहले' थीम के तहत, इस पहल का मकसद शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बच्चन की भरोसेमंद इमेज फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस की पहुंच और सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जिससे भारतीय परिवार समय पर इंश्योरेंस के फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- जून 2026 में भारत का मर्चेडाइज़ ट्रेड डेफिसिट बढ़कर \$30.43 बिलियन हो गया, जो मई में \$28.21 बिलियन और एक साल पहले \$19.10 बिलियन था। मर्चेडाइज़ एक्सपोर्ट घटकर \$40.41 बिलियन हो गया, जबकि इम्पोर्ट \$70.84 बिलियन रहा। बढ़ते डेफिसिट की वजह कूड ऑयल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कीमती मेटल्स का ज्यादा इम्पोर्ट और धीमी एक्सपोर्ट ग्रोथ थी। इस ट्रेड से करंट अकाउंट डेफिसिट, रुपये की स्टेबिलिटी और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर पड़ता है।
- खाने की चीज़ों, बेसिक मेटल, केमिकल और मिनरल ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) इन्फ्लेशन मई के 9.68% से जून 2026 में बढ़कर 9.87% हो गया। रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़कर 4.38% हो गया, जबकि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 5.32% पर पहुंच गया। हालांकि कच्चे तेल की कम कीमतों की वजह से फ्यूल इन्फ्लेशन कम हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन ऊंचा बना रहा। खाने और कमोडिटी की कीमतों पर लगातार दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है।
- EaseMyTrip ने झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ एक MoU साइन किया है ताकि राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक, इको-टूरिज्म और आदिवासी विरासत को बढ़ावा दिया जा सके। इस पार्टनरशिप में डिजिटल कैम्पेन और EasyDarshan प्लेटफॉर्म के ज़रिए बैचनाथ धाम, झरने, जंगल, वाइल्डलाइफ पार्क और हेरिटेज साइट्स जैसी जगहों की मार्केटिंग की जाएगी। इस पहल का मकसद टूरिस्ट की संख्या बढ़ाना, रोज़गार पैदा करना, लोकल बिज़नेस को सपोर्ट करना और असली ट्रेवल एक्सपीरियंस दिखाकर और पूरे भारत में डिजिटल विज़िबिलिटी को बेहतर बनाकर झारखंड की टूरिज्म इकॉनमी को मजबूत करना है।
- MRF लिमिटेड को ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 - 2026 रिपोर्ट में भारत का सबसे कीमती और सबसे मजबूत टायर ब्रांड बताया गया। इसे 87.7/100 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स (BSI) स्कोर के साथ दुनिया भर में तीसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड भी मिला। यह पहचान MRF के मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट लीडरशिप, कस्टमर के भरोसे और ब्रांड वैल्यू को दिखाती है। 1946 में शुरू हुई MRF ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, खेती की मशीनरी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए टायर बनाती है, जिससे भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में इसकी लीडरशिप और मजबूत होती है।
- मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने 2024-25 को बेस ईयर मानकर भारत का पहला इंडेक्स ऑफ़ सर्विसेज़ प्रोडक्शन (ISP) लॉन्च किया। 19 फॉर्मल सर्विसेज़ सेक्टर को कवर करते हुए, यह इंडेक्स पॉलिसी बनाने और इकोनॉमिक मॉनिटरिंग के लिए मंथली डेटा देगा। पहली रिपोर्ट में दिखाया गया कि अप्रैल 2026 में 14 सेक्टर में डबल-डिजिट ग्रोथ हुई, जिसमें अकॉमोडेशन एंड फूड सर्विसेज़ (37.2%), रिटेल (30.8%), और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ (28.7%) सबसे आगे रहे। इंडेक्स GST डेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड और सर्वे का इस्तेमाल करता है, और मंथली रिलीज़ 29 तारीख को शेड्यूल की गई है।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 13 जुलाई 2026 तक भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.4% बढ़कर ₹ 6.51 लाख करोड़ हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन ₹ 2.40 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स बढ़कर ₹ 3.85 लाख करोड़ हो गया। ग्राँस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ₹ 7.74 लाख करोड़ रहा, जिसमें रिकंड बढ़कर ₹ 1.22 लाख करोड़ हो गया। बढ़ते टैक्स कम्प्लायंस, मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग्स और ज्यादा मार्केट एक्टिविटी ने इस बढ़ोतरी में योगदान दिया, जिससे भारत की फिस्कल पोজीशन मजबूत हुई।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्पेसिफाइड नॉन-फाइनेंशियल एसेट्स (SNFAs) के लिए एक प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पेश किया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। बैंकों, NBFCs, RRBs, SFBs और AIFIs पर लागू होने वाला यह फ्रेमवर्क एसेट एक्विजिशन, वैल्यूएशन, रिकवरी और डिस्पोजल को स्टैंडर्ड बनाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल गवर्नेंस में सुधार होता है।
- डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न ने AI-पावर्ड मल्टीलिंगुअल बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक MoU साइन किया है। सेवा/संचालन पहल के लिए भाषिनी के तहत, कस्टमर AI ट्रांसलेशन, स्पीच टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके अपनी पसंदीदा भारतीय भाषाओं में बैंकिंग सर्विस एक्सेस करेंगे। इस इंटिग्रेशन का मकसद डिजिटल बैंकिंग एक्सेस को बेहतर बनाना है, खासकर ग्रामीण और रीजनल इलाकों में, साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना और लैंग्वेज-फ्रेंडली बैंकिंग सॉल्यूशंस के ज़रिए फाइनेंशियल इनक्लूजन को आगे बढ़ाना है।
- सरकार ने 16 जुलाई 2026 से पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) में बदलाव किया है। डीज़ल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, जबकि पेट्रोल ड्यूटी कम की गई। इन बदलावों का मकसद देश में फ्यूल की सही उपलब्धता पक्का करना, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के समय में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट को रोकना और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत करना है। पेट्रोल और डीज़ल पर घरेलू एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- RBI फाइनेंशियल इन्क्लूजन इंडेक्स 67 (FY25) से बढ़कर 70 (FY26) हो गया, जो बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, इंश्योरेंस, पेंशन, इन्वेस्टमेंट और पोस्टल फाइनेंशियल सर्विसेज़ तक ज़्यादा पहुँच को दिखाता है। 2021 में शुरू किया गया यह इंडेक्स एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी को मापता है। ग्रोथ फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज़ को ज़्यादा अपनाने, फाइनेंशियल इन्क्लूजन, डिजिटल फाइनेंस, इनक्लूसिव ग्रोथ और सरकारी वेलफेयर बेनिफिट्स की अच्छे से डिलीवरी से हुई।
- FICCI-डेलॉइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2030 तक USD 600 बिलियन तक पहुँच जाएगी। अभी सिर्फ 12-13% खेती की चीज़ों की प्रोसेसिंग होती है, इसलिए यह सेक्टर वैल्यू एडिशन, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की इनकम बढ़ाने के बड़े मौके देता है। ग्रोथ को AI, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, शहरीकरण और सरकारी कोशिशों से सपोर्ट मिलेगा, जिससे भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम मज़बूत होगा।

किताबें और लेखक समाचार

- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी यादों की किताब, "द सेकंड ऑर्बिट: बिलीफ ऑफ़ ए मैन... ड्रीम्स ऑफ़ 1.4 बिलियन हार्ट्स" रिलीज़ की। इसमें इंडियन एयर फ़ोर्स के फ़ाइटर पायलट से लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए एक्सिओम-4 मिशन पर एस्ट्रोनॉट बनने तक के उनके सफ़र के बारे में बताया गया है। एयर चीफ़ मार्शल अमर प्रीत सिंह द्वारा लॉन्च की गई इस किताब में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, मिशन की

तैयारी और भारत की बढ़ती स्पेस महत्वाकांक्षाओं पर रोशनी डाली गई है। यह राकेश शर्मा को सम्मान भी देती है और युवा भारतीयों को STEM की पढ़ाई करने और भविष्य में इंसानों के साथ स्पेस में खोज में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है।

- वाइस-प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने "द वाइस ऑफ़ जस्टिस: जस्टिस गवर्न स्प्रीक्स" रिलीज़ की, जिसे प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार ने एडिट किया है और थॉमसन रॉयटर्स ने CLEA के साथ मिलकर पब्लिश किया है। इस किताब में पूर्व चीफ़ जस्टिस बीआर गवई के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ज्यूडिशियल फिलॉसफी, सोशल जस्टिस और कानून के राज पर भाषण और विचार शामिल हैं। इवेंट के दौरान, वाइस-प्रेसिडेंट ने संविधान को एक जीवित डॉक्यूमेंट बताया और न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा प्रो-बोनी कानूनी सेवाओं की अपील की।

नियुक्तियाँ/इस्तीफ़े

- डॉ. श्रीनिवास कुमार तुम्माला को मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्थ साइंसेज (MoES) का सेक्रेटरी बनाया गया है। वे एक जाने-माने ओशनोग्राफर हैं, उन्होंने सैटेलाइट ओशनोग्राफी, क्लाइमेट सर्विसेज़, सुनामी वॉर्निंग सिस्टम और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में योगदान दिया है। INCOIS के डायरेक्टर के तौर पर, उन्होंने इंडियन सुनामी अर्ली वॉर्निंग सेंटर बनाने में मदद की।

रक्षा समाचार

- भारतीय वायु सेना (IAF) ने अभ्यास पिच ब्लैक 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया में राफेल लड़ाकू जेट तैनात किए। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना (RAAF) द्वारा आयोजित, यह अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी, वायु युद्ध प्रशिक्षण और भारत-प्रशांत रक्षा सहयोग को बढ़ाता है।
- ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 को इंडियन नेवी और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सिज़ (CMF) ने मिलकर चलाया है। इसका मकसद समुद्री सुरक्षा, इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाना, पाइरेसी, आतंकवाद और गैर-कानूनी ट्रेफ़िकिंग से निपटना और नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था को मज़बूत करना है।
- भारतीय नौसेना INS मालवन को चालू करेगी, जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा बनाया गया दूसरा माहे-क्लास एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है, जिसमें 80% स्वदेशी सामग्री है। यह तटीय निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करता है और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है।

पुरस्कार और सम्मान

- कोलंबिया में हुए 56वें इंटरनेशनल फ़िज़िक्स ओलंपियाड (IPhO) 2026 में भारत ने एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की, जिसमें टीम के सभी पाँच सदस्यों ने गोल्ड मेडल जीते। भारत ने चीन, कज़ाकिस्तान, रूस, साउथ कोरिया और ताइवान के साथ मेडल टैली में टॉप किया। मेडल जीतने वालों में कनिष्क जैन, रिद्धेश बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी शामिल थे। HBCSE से ट्रेनिंग पाने वाली इस टीम ने सिर्फ़ गोल्ड या सिल्वर मेडल जीतने के भारत के दस साल पुराने रिकॉर्ड को जारी रखा, जिससे इंटरनेशनल साइंस एजुकेशन में भारत की काबिलियत और मज़बूत हुई।

- मशहूर तमिल कवि और गीतकार आर. वैरामुथु को भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान, 60वां ज्ञानपीठ अवॉर्ड (2025) मिला। वे अकिलन और जयकांतन के बाद यह अवॉर्ड पाने वाले तीसरे तमिल लेखक बन गए हैं। डॉ. करण सिंह द्वारा नई दिल्ली में दिए गए इस अवॉर्ड में ₹ 11 लाख, देवी वाग्देवी की एक ब्रॉन्ज़ मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। वैरामुथु को तमिल साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए पहचान मिली, जिसमें कल्लिकट्ट इतिहासम जैसी रचनाएँ शामिल हैं, जिसने साहित्य अकादमी अवॉर्ड जीता।

खेल समाचार

- लैंडा नोस्कोवा ने साथी चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। विंबलडन 2026 के विमेंस सिंगल्स फाइनल में 6-2, 5-7, 6-3 से जीत हासिल की। सिर्फ 21 साल की उम्र में, वह लगातार नौवीं बार विंबलडन विमेंस चैंपियन बनीं। इस जीत ने मार्केटा वोंद्रोसोवा (2023) और बारबोरा क्रेजसिकोवा (2024) के टाइटल जीतने के बाद विंबलडन में चेक रिपब्लिक का दबदबा और बढ़ा दिया। नोस्कोवा ने यह इमोशनल जीत अपनी गुज़र चुकी मां को डेडिकेट की, जबकि मुचोवा की उनके फाइटिंग स्पिरिट के लिए तारीफ़ की गई। इस ऐतिहासिक ऑल-चेक फाइनल ने ग्लोबल स्टेज पर चेक विमेंस टेनिस की ज़बरदस्त ताकत और गहराई को दिखाया।
- दुनिया के नंबर 1 जैनिन सिनर ने विंबलडन में सिंगल्स का अपना टाइटल सफलतापूर्वक डिफेंड किया, उन्होंने जर्मन खिलाड़ी पर लगातार 10वीं जीत के लिए अलेक्जेंडर ज़ेबरेव को चार सेट में हराया। महिलाओं के फाइनल में, लैंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुचोवा को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता, और लगातार नौवीं बार पहली बार महिला चैंपियन बनीं। हेनरी पैटन और हैरी हेलियोवारा ने मैन डबल्स जीता, गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लादेनोविच ने महिला डबल्स जीता, जबकि मार्सेलो एरेवालो और जेलेना ओस्टापेंको ने मिक्सड डबल्स का टाइटल जीता, जिससे विंबलडन 2026 एक यादगार चैंपियनशिप बन गया।
- भारतीय पेसर क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड विमेंस के खिलाफ शानदार पांच विकेट लेकर मशहूर लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने टैमी ब्यूमोंट, माइया बाउचियर, नैट साइवर-ब्रंट, एलिस कैप्सी और लॉरेन बेल को आउट किया, और यह सम्मान पाने वाली 15वीं भारतीय बॉलर बनीं। कपिल देव, विशन सिंह बेदी, इशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गजों के साथ, गौड़ की इस उपलब्धि ने भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक अहम पल को चिह्नित किया और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी बढ़ती अहमियत को दिखाया।
- यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं, उन्होंने इंग्लैंड विमेंस के खिलाफ 113 रन बनाए। पहली इनिंग में सिर्फ 12 रन बनाने के बाद, उन्होंने 145 गेंदों में सेंचुरी बनाकर शानदार वापसी की। इस पारी ने उन्हें मशहूर लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड में जगह दिलाई और यह उनकी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी थी। यास्तिका लॉर्ड्स में टेस्ट सेंचुरी बनाकर राहुल द्रविड़, सौरव

गांगुली, दिलीप वेंगसरकर, वीनू मांकड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे दिग्गज भारतीय बैट्समैन में भी शामिल हो गई।

- भारतीय शूटर नीरू ढांडा ने इटली के लोनोटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं का ट्रैप गोल्ड मेडल जीता, जिससे भारत को इस सीज़न का पहला शॉटगन गोल्ड मिला। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 121/125 के साथ टॉप किया और फिर एक रोमांचक फाइनल में फ्रांस की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कैरोल कॉर्मेनियर को हराया। इस जीत ने ढांडा का पहला इंडिविजुअल ISSF वर्ल्ड कप मेडल बनाया, जिसमें अल्माटी में पहले जीता गया उनका मिक्सड ट्रैप ब्रॉन्ज़ मेडल भी शामिल है। उनके शानदार प्रदर्शन ने इंटरनेशनल शूटिंग और महिलाओं के ट्रैप इवेंट्स में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाया।
- पूर्व कप्तान हीथर नाइट ने लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ ऐतिहासिक महिला टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की, जिससे उनके शानदार 16 साल के करियर का अंत हो गया। उन्होंने 320 इंटरनेशनल मैच खेले, 7,988 रन बनाए और 2017 ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को जीत दिलाई। नाइट अब द हंड्रेड में लंदन स्पिरिट की जनरल मैनेजर के तौर पर काम करेंगी। उनके रिटायरमेंट से इंग्लैंड के सबसे सफल करियर में से एक और महिला क्रिकेट में एक अहम चैंप्टर का अंत हो गया है।
- लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर पहले विमेंस टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रच दिया। यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला बनीं, जबकि क्रांति गौड़ पांच विकेट लेकर मशहूर लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला बॉलर बनीं। हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में, भारत की इस बड़ी जीत ने टीम के दबदबे को दिखाया और इस आइकॉनिक स्टेज पर भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक बड़ी कामयाबी को दिखाया।
- दिल्ली ने 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होने वाली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के ऑफिशियल मैस्कॉट 'मयूर' को लॉन्च किया। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित यह मैस्कॉट एकता, विविधता, दोस्ती और खेल भावना का प्रतीक है। इसमें लगभग 35 कॉमनवेल्थ देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा लॉन्च की गई इस चैंपियनशिप को दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) मिलकर ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं, जो दिल्ली को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन के तौर पर दिखाता है।

शिखर सम्मेलन और सम्मेलन समाचार

- जल शक्ति मंत्रालय ने सीआर पाटिल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जल संसाधन विभागों के सबसे सीनियर सचिवों का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। कॉन्फ्रेंस में वॉटर गवर्नेंस, सिंचाई की क्षमता, डैम सुरक्षा, जलाशय मैनेजमेंट, कैच द रेन कैम्पेन, स्टेट वॉटर रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क और मॉडल स्टेट वॉटर अवॉर्ड्स पर फोकस किया गया। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सेंट्रल वॉटर कमीशन और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों ने सेंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने और सस्टेनेबल वॉटर कंजर्वेशन और लॉन्ग-टर्म वॉटर सिक्योरिटी के लिए सुधारों में तेजी लाने के लिए इसमें हिस्सा लिया।

योजना समाचार

- उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा जानवरों, नीलगाय और जंगली सूअरों से फसलों को बचाने के लिए UP खेत सुरक्षा योजना 2026 शुरू की है। योग्य किसानों को सोलर पावर वाली इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी मिलेगी, जिसमें प्रति किलोमीटर ₹ 1.43 लाख की मदद मिलेगी, जबकि SC/ST, छोटे और सीमांत किसानों को 70% तक सब्सिडी मिल सकती है। फेंसिंग में सुरक्षित लो-वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स का इस्तेमाल होता है जो जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए रोकते हैं। इस पहल का मकसद फसल के नुकसान को कम करना, खेती की पैदावार में सुधार करना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना और गांव की रोजी-रोटी को मजबूत करना है।
- एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने एमनेस्टी स्कीम 2026 शुरू की है, जो एग्जिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले ऑर्गनाइजेशन को एक बार में छह महीने का कम्प्लायंस विंडो देती है। यह स्कीम एलिजिबल कंपनियों को EPFO रीजनल ऑफिस के ज़रिए रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके पेंडिंग लीगल फॉर्मैलिटीज़ पूरी करने में मदद करती है। इसका मकसद रिटायरमेंट सेविंग्स को प्रोटेक्ट करते हुए गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी कम्प्लायंस और एम्प्लॉई सोशल सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। एम्प्लॉयर-मैनेज्ड PF ट्रस्ट में एक जैसे कम्प्लायंस को बढ़ावा देकर, यह पहल लीगल अनिश्चितता को कम करती है, एम्प्लॉई के बीच कॉन्फिडेंस को मजबूत करती है, और प्रोविडेंट फंड सिस्टम के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाती है।
- उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) स्कीम 2026 सभी 75 जिलों में पारंपरिक इंडस्ट्री, कारीगरों और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रही है। बेनिफिशियरी को ₹ 25 लाख तक का लोन, 25% मार्जिन मनी सब्सिडी, स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग सपोर्ट और एक्सपोर्ट असिस्टेंस मिलता है। यह स्कीम वाराणसी सिल्क, लखनऊ चिकनकारी, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, कन्नौज परफ्यूम और भदोही कालीन जैसे मशहूर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देती है। इसका मकसद कल्चरल हेरिटेज को बचाना, रोजगार पैदा करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारना और घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट के मौकों को बढ़ाना है।
- दिल्ली सरकार ने अपनी प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है, क्योंकि यह रक्षा बंधन 2026 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। इस स्कीम में योग्य महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के ज़रिए हर महीने ₹ 2,500 की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है। इसका मकसद महिलाओं की आर्थिक आज़ादी और सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। फ़ाइनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की घोषणा अभी बाकी है। यह पहल आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए सरकार के बड़े वेलफेयर कमिटमेंट्स में से एक है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार

- जापान के JAXA ने नोशिरो रॉकेट टेस्टिंग सेंटर में RV-X रीयूजेबल रॉकेट का पहला लिफ्ट-ऑफ और लैंडिंग टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रोटोटाइप ने 40 सेकंड की उड़ान पूरी की, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बाद सुरक्षित रूप से लैंडिंग से पहले 10-11 मीटर तक पहुंचा। रॉकेट रिकवरी, सटीक लैंडिंग, गाइडेंस और रीयूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए डेवलप किया गया यह प्रोग्राम भविष्य में स्पेस लॉन्च की लागत को कम करने का लक्ष्य रखता है। 160 से ज्यादा कंबेशन टेस्ट के बाद, सफल डेमोस्ट्रेशन रीयूजेबल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में जापान की भूमिका को मजबूत करता है और फ्रांस और जर्मनी के साथ इंटरनेशनल CALLISTO रीयूजेबल रॉकेट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है।
- ISRO ने गगनयान कू मॉड्यूल के लिए तीन बड़े क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जिसमें कू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम (CMUS), कू-सर्विस अम्बिलिकल यूनिट (CSU-2), और एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम को वैलिडेट किया गया है। ये सिस्टम भारत के पहले ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन के दौरान सुरक्षित स्प्लैशडाउन, फ्लोटेशन, पैराशूट डिप्लॉयमेंट, री-एंट्री और एस्ट्रोनॉट की रिकवरी सुनिश्चित करते हैं। 12 जुलाई 2026 को किए गए इन टेस्ट से मिशन की तैयारी में काफी सुधार हुआ है और ज़रूरी सेफ्टी सिस्टम के भरोसेमंद होने की पुष्टि हुई है। यह उपलब्धि लो अर्थ ऑर्बिट में भारत के पहले स्वदेशी ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन, गगनयान को लॉन्च करने की दिशा में एक और मील का पत्थर है।
- सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (CeNS) के साइंटिस्ट्स ने एक सेल्फ-पावर्ड बियरेबल अमोनिया गैस सेंसर बनाया है जो 319 ppb जितनी कम कंसंट्रेशन का भी पता लगा सकता है। VOx/VS₂ हेट्रोस्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बनाया गया यह फ्लेक्सिबल सेंसर, बिना किसी बाहरी हीटिंग के कमरे के तापमान पर अच्छे से काम करता है। यह हाई सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी और रियल-टाइम अलर्ट देता है, जिससे यह इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थकेयर, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग और स्मार्ट टेक्स्टाइल एप्लीकेशन के लिए कम एनर्जी इस्तेमाल करते हुए काम का है।
- ISRO के पूर्व चेयरमैन एस. सोमनाथ अग्रिकुल कॉसमॉस के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में ऑब्ज़र्वर के तौर पर शामिल हुए। चेन्नई का यह प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप मिशन 02 की तैयारी कर रहा है, जो रीयूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी और बूस्टर रिकवरी पर फोकस करता है। लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट में सोमनाथ की एक्सपर्टीज़ भारत के पब्लिक और प्राइवेट स्पेस सेक्टर के बीच कोलेबोरेशन को मजबूत करेगी, इनोवेशन, कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज़ और देश की एक लीडिंग ग्लोबल स्पेस पावर बनने की महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करेगी।

महत्वपूर्ण दिन समाचार

- वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई 2026 को "शेयर्ड फ्यूचर के लिए स्किल्स" थीम के साथ मनाया जाता है। 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा शुरू किया गया यह दिन युवाओं में टेक्निकल, वोकेशनल, डिजिटल और लाइफ स्किल्स को बढ़ावा देता है। यह टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग (TVET), लाइफलॉन्ग लर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयबिलिटी पर जोर देता है। 2026 की थीम AI, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन इकॉनमी स्किल्स, इनोवेशन और सरकारों, इंडस्ट्रीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच कोलेबोरेशन पर जोर देती है ताकि फ्यूचर के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाई जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) को हासिल किया जा सके।
- वर्ल्ड लिसनिंग डे हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है ताकि ध्यान से सुनने, अक्यूस्टिक इकोलॉजी और कुदरती और इंसानों के बनाए साउंडस्केप के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ल्ड लिसनिंग प्रोजेक्ट ने 2010 में इसे शुरू किया था, यह रेमंड मरे शेफर की याद में मनाया जाता है और नॉइज़ पॉल्यूशन कम करने, पर्यावरण बचाने और साउंड के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- 16 जुलाई को पुरी, ओडिशा में मनाई गई। यह भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की सालाना यात्रा का प्रतीक है। इस त्योहार में लकड़ी के बड़े रथ, पारंपरिक रस्में जैसे पहंडी, हेरा पंचमी, बहुदा यात्रा और सुना वेशा शामिल हैं, और यह लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यह भक्ति, समानता और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक है।
- वर्ल्ड स्लेक डे हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है ताकि सांपों की इकोलॉजिकल अहमियत के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और वाइलडलाइफ कंज़र्वेशन को बढ़ावा दिया जा सके। 2009 में शुरू हुआ

यह दिन चूहों की आबादी को कंट्रोल करके इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में सांपों की भूमिका पर जोर देता है। भारत में लगभग 300 तरह के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कई वाइलडलाइफ़ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के तहत सुरक्षित हैं। इस दिन का मकसद गलतफहमियों को दूर करना और सांपों के बारे में साइंटिफिक समझ को बढ़ावा देना भी है।

- वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस रोम स्टैच्यूट (1998) की याद में मनाया जाता है, जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) की स्थापना की थी। यह दिन ह्यूमन राइट्स, कानून का राज, जवाबदेही, पीड़ितों के लिए न्याय और नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के खिलाफ इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देता है।

निधन

- पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। 1995 से 2013 तक अमीर के तौर पर काम करते हुए, उन्होंने नॉर्थ फील्ड गैस रिज़र्व के डेवलपमेंट, LNG प्रोडक्शन के विस्तार और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की स्थापना के ज़रिए कतर को बदल दिया। उन्होंने अल जज़ीरा भी लॉन्च किया और 2022 FIFA वर्ल्ड कप की मेज़बानी की नींव रखी। उनके निधन के बाद, कतर ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत नेताओं ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व और स्थायी वैश्विक विरासत को श्रद्धांजलि दी।
- क्रिकेट के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वेस्टइंडीज के इस महान खिलाड़ी ने 8,032 टेस्ट रन बनाए, 235 टेस्ट विकेट लिए, उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड 365 * बनाया, और फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने। उन्हें 1975 में नाइटहुड दिया गया और ICC हॉल ऑफ़ फेम में शामिल किया गया, जिससे वे एक असाधारण क्रिकेट विरासत छोड़ गए।

स्टेटिक टेकअवे

पहलू	विवरण
बिहार	CM: सम्राट चौधरी, गवर्नर: आरिफ खान, राजधानी: पटना
झारखंड	CM: हेमंत सोरेन, गवर्नर: संतोष गंगवार, राजधानी: रांची
केरल	मुख्यमंत्री: वीडी सतीशन, गवर्नर: आर आर्लेकर, राजधानी: तिरुवनंतपुरम
ओडिशा	CM: मोहन माझी, गवर्नर: हरिबाबू खंभापति, राजधानी: भुवनेश्वर
असम	CM: हिमंत सरमा, गवर्नर: लक्ष्मण आचार्य, राजधानी: दिसपुर
कर्नाटक	CM: डीके शिवकुमार, गवर्नर: थावर चंद गहलोत, राजधानी: बेंगलुरु
महाराष्ट्र	CM: देवेन्द्र फडणवीस, गवर्नर: जिष्णु देव वर्मा, राजधानी: मुंबई
आंध्र प्रदेश	CM: चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर: अब्दुल नज़ीर, राजधानी: अमरावती
मध्य प्रदेश	CM: मोहन यादव, गवर्नर: मंगूभाई पटेल, राजधानी: भोपाल
स्वतंत्र	CM: कोनराड संगमा, गवर्नर: सीएच विजयशंकर, राजधानी: शिलांग
तमिलनाडु	CM: जोसेफ विजय, गवर्नर: आर. आर्लेकर, राजधानी: चेन्नई

वीकली वन लाइनर्स 13 से 19 जुलाई, 2026

पहलू	विवरण
फ्रांस	राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रों
इंगलैंड	प्रधानमंत्री: कीर स्टारमर
संयुक्त राज्य अमेरिका	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प
जर्मनी	चांसलर: फ्रेडरिक मर्ज़
इटली	प्रधानमंत्री: जॉर्जिया मेलोनी
भारतीय रिजर्व बैंक	अध्यक्ष: संजय मल्होत्रा
सेबी	चेयर पर्सन: तुहिन कांता पांडे





ALL EXAMS, **ONE** SUBSCRIPTION

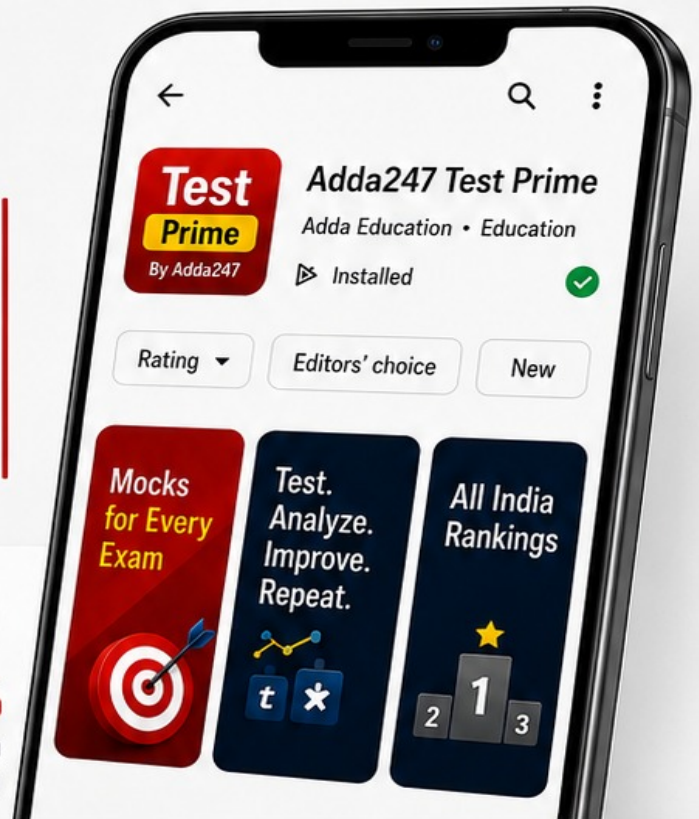


Test. Analyze. Improve. Repeat.



*Don't just
prepare.
Perform.*

Test Prime – built only
for mock tests.



1,50,000+
Mock Tests



25,000+
Previous Year
Papers



800+
Exam
Covered



500%
Refund on
Selection



5 lakh+
Free Quizzes



Daily
Free PDFs



Top Alerts
Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- ✓ Multilingual
- ✓ Detailed Solution
- ✓ Strong and Weak Areas
- ✓ All India Rankings



Safe & Reliable



Trusted by
Lakhs of Aspirants



Your Success,
Our Mission



**DOWNLOAD
TEST PRIME**

Your Success Partner!

